राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 81 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,23 सितम्बर 2021, मूल्य रु. 1.50

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में नामित वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल वी आर चौधरी से मुलाकात की।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार रुपए मुआवजा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मरने वालों लोगों के परिवार को ?50000 अनुग्रह राशि दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश जारी किया है. एनडीएमए ने राज्यों द्वारा राज्य आपदा राहत कोष से भुगतान करने के लिए ?50 हजार निर्धारित किया है.

हलफनामे में कहा है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी.कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था. मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी

करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आप जब तक कदम उठाएंगे, तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी.

कोर्ट का पिछला आदेश

30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था. कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे. कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था.मामले के याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है.

यह मामला जस्टिस एम आर शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच में लगा था. सुनवाई की शुरुआत में ही एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को सूचित किया था कि अब तक हलफनामा दाखिल नहीं हो पाया है. भाटी ने इसके लिए 10 दिन का समय मांगा था.

कोर्ट में मौजूद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि मामला अभी सरकार के पास विचाराधीन है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेंच के अध्यक्ष जस्टिस शाह ने कहा था कि आदेश आए हुए लंबा समय बीत चुका है. सरकार जब तक कुछ करेगी, तब तक तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी. कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले भी समय मांग चुकी है. अब वह 11 सितंबर तक जवाब दाखिल कर दे.

दुरुस्त होगी डिजिटल एजुकेशन की गुणवत्ता, बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी

नई दिल्ली । कोरोना संकटकाल में पढ़ाई के लिए अनिवार्य जरूरत बन चुकी डिजिटल एजुकेशन की गुणवत्ता को मजबूती देने और सभी तक उसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पहल तेज की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को इसे लेकर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। साथ ही इसकी गुणवत्ता और प्रसार को बेहतर रखने के लिए स्कूली शिक्षा सचिव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाने का सुझाव दिया है। जिसमें दूसरे संबंधित मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को डिजिटल एजुकेशन की गुणवत्ता की समीक्षा का निर्देश दिया- शिक्षा मंत्री प्रधान का इस दौरान पूरा जोर डिजिटल एजुकेशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। ने और उसे रुचिकर बनाने का लकर था। इसके लिए उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें, जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, वह बच्चों के लिए कितना ग्राह्य है। स्वयंप्रभा टीवी चैनेल में दिखाई जाने वाली सामग्री को भी उन्होंने रुचिकर बनाने का सुझाव दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इसकी पहुंच अंतिम छोर तक बैठे बच्चों तक होनी चाहिए।

प्रधान ने इस दौरान स्कूली शिक्षा सचिव की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय कमेटी में जिन मंत्रालय व विभागों को शामिल करने का सुझाव दिया है, उनमें स्कूली और उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास, इलेक्ट्रानिक्स और आइटी, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , प्रसार भारती, अंतरिक्ष विभाग आदि प्रमुख हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने कोरोना संकटकाल में सभी तक डिजिटल एजुकेशन की पहुंच को आसान बनाने के लिए सेटेलाइट टीवी को विस्तार देने की पहल की थी। संसदीय समिति ने इसको लेकर कई राज्यों को तलब भी दिया था।

निरंजन अखाड़ा ने महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी को माना संदिग्ध

मौत की सीबीआई जांच होगी

■ योगी सरकार ने की सिफारिश, ■ उत्तराधिकारी को लेकर गहराया विवाद,
■ संदीप तिवारी की भी गिरफ्तारी, ■ पीएम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत

प्रयागराज (एजेंसी)।

अभा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी उलझ गई है। इस बीच महंत नरेंद्र गिरि मृत्यु से जुड़े मामले की जांच उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई द्वारा किए जाने की सिफारिश की है। अभा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि सोमवार को संदिग्ध हालत में फंदे पर लटके मिले थे। अब निरंजनी अखाड़ा के रविंद्र पुरी ने बड़ा बयान दिया है। रविंद्र पुरी ने कहा कि फांसी में सिर के पीछे चोट कैसे हो सकती है? ना जुबान चढ़ी, न आंखें।। तो ये खुदकुशी कैसे हो सकती है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बलवीर गिरि को अखाड़ा परिषद का प्रमुख मानने से इंकार

अब, अखाड़ा परिषद के महासचिव महंत हरी गिरि महाराज हैं, उन्होंने बलवीर गिरि के नाम पर सवाल उठाया है। रविंद्र पुरी ने भी एक न्यूज चैनल को बताया कि ऐसे कैसे वो बन जाएंगे अध्यक्ष? यह फैसला अखाड़े का है, सर्वसम्मति से निर्णय 16 दिन बाद लिया जाएगा।

आनंद गिरि, आद्या को 14 दिन की जेल, मामले में तीसरी गिरफ्तारी

अभा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी के शिष्य और हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महंत नरेन्द्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार योग गुरु आनंद गिरि और बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी से एसआईटी पिछले कई घंटे से पूछताछ कर रही थी। एसआईटी ने बुधवार शाम चार बजे दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आद्या तिवारी के सुपुत्र संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। महंत के शव का परीक्षण बुधवार को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में आठ बजे शुरू हुआ जो ढाई घंटे चला। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं मिला। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है।

बाघम्बरी गद्दी मठ में दी गई भू-समाधि

प्रयागराज, (एजेंसी) साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरि को बुधवार को श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी में भू-समाधि दी गई। सुसाइड नोट में उनकी अंतिम इच्छा थी कि समाधि श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी पार्क में नीबू के पेड़ के पास गुरु जी के बगल दी जाए। अखाड़े के बड़े संत और महात्माओं ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसी स्थान पर वेद मंत्रों के साथ सभी 13 अखाड़ों के बड़े संत , महंत और साधु-सतों की उपस्थिति में भू-समाधि दी गई। महंत को 12 फिट के गढ्ढे में तैयार गुप्त द्वारनुमा स्थान में सिद्ध योग मुद्रा में घंटे-घड़ियाल और मंत्रोचार के बीच समाधि में बैठाया गया। उनके पास उनके नित्य पूजा की अपयोग की सभी वस्तुओं को रखा गया। महंत के भू समाधि में अखाड़ों के महामंडलेश्वर, आचार्य और बड़े संत महात्माओं ने वैष्णव सम्प्रदाय के परंपराओं को ध्यान में रखकर विधि विधान से शंखनाद के बीच क्रमशः पुष्प, नमक, चीनी, घी,दूध, बेलपत्र पंचामृत आदि भू समाधि डाले गए।

रणनीतिक साझीदारी को सशक्त बनाएंगे: पीएम

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा को भारत एवं अमेरिका के बीच समग्र वैश्विक रणनीतिक साझीदारी को सशक्त बनाने, भारत के रणनीतिक साझीदार जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध मजबूत बनाने तथा महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने का अवसर करार दिया है।

श्री मोदी अमेरिका पहुंचे। इससे पूर्व अपने वक्तव्य में यह आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति श्री बिडेन के साथ मिलकर भारत अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीतिक साझीदारी की समीक्षा करेंगे और समान हितों के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि वह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे और दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपाय खोजेंगे।

कोविड-19 समिट

भारत चला रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान: पीएम मोदी

कोविड-19 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि, हमें महामारी के आर्थिक प्रभावों को दूर करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उस अंत तक, वैक्सीन प्रमाण-पत्रों की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए। जैसे-जैसे नए भारतीय टीके विकसित होते हैं, हम मौजूदा टीकों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। जैसे-जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता है, हम दूसरों को भी वैक्सीन की आपूर्ति फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे। इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखना चाहिए। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। हाल ही में, हमने एक दिन में लगभग 25 मिलियन लोगों को टीका लगाया।

पांच राज्यों के बाद अब 'आप' की हिमाचल प्रदेश पर नजर, 68 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि नवंबर 2022 में होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में वह सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के बाद हिमाचल छठा राज्य है जहां आप 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है. आप हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने दिल्ली मॉडल का नारा देते हुए सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है.

रविवार को, अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से पलायन को समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठाने का वादा किया, और अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य के लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता और 80 प्रतिशत नौकरी कोटा का आश्वासन दिया.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, वह उत्तराखंड के लोगों के लिए वही करेंगे जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया. उन्होंने

कहा, रोजगार विभाग में 84 प्रतिशत नौकरियां खाली हैं. पिछले सात वर्षों में केवल 440 लोगों को नौकरी मिलने के साथ, केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को छह महीने में एक लाख नौकरी देने का वादा किया है. उन्होंने छह सूत्री धोखा देने की गारंटी देवभूमि के लोगों से किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत 13 लाख युवाओं को 7,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए.

इस बीच, 2022 के पंजाब चुनाव जीतने के लिए, आप ने पहले ही राज्य के लोगों को सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है. आप के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने एक साक्षात्कार में कहा कि राज्य के लोग अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को अगले चुनाव में मौका देना चाहते हैं. क्योंकि अकाली दल 'अप्रासंगिक' हो गया है, जबकि अब तक के इतिहास में कांग्रेस सबसे अधिक निकम्मी सरकार रही है.

आप सांसद और पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुने जाने की संभावनाओं पर, चड्ढा ने कहा, ÷मैं आप के सीएम उम्मीदवार की केवल तीन विशेषताएं कह सकता हूं. एक यह है कि वह पंजाब राज्य का होगा, वह पंजाब की 2.8 करोड़ आबादी से होगा और तीसरा वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पंजाब की 'आन बान शान' कहा जा सकता हो. इस साल जून में, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा सिख समुदाय से होगा.

देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 83 करोड़ लगाए गए डोज, केंद्र का वैक्सीनेशन को तेज करने पर जोर

नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच बुधवार शाम 7 बजे तक 64 लाख (64,98,274) से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए हैं. देर रात तक यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. अब तक 83 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में सबसे कमजोर तबके को कोरोना से बचाने के लिए एक टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है. देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया गया. फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है. कोरोना के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था.

उसने कहा कि टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया है. इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना दी जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके.

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है. टीके की उपलब्धता के नए चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री दिए जा रहे हैं.

चीन के साथ तनाव से निपटने में कोरोना रोधी उपायों से भारतीय सेना को फायदा हुआ: सेना प्रमुख

नई दिल्ली । पिछले साल की शुरुआत में कोरोना से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए उपायों से पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रमण से निपटने में इसका फायदा हुआ। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को यह बात कही। देश में पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण के कारण लाकडाउन लागू होने के बाद, भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के बीच कोविड को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए और उन पर प्रतिबंध लगाया और बाहरी दुनिया के साथ उनके संपर्क को कम कर दिया। इसके तुरंत बाद पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण शुरू हो गया था।

जनरल नरवणे ने 21 वीं सदी के वीनिंग द 21 स्ट सेंचुरी वारः ट्रांसफार्मिंग इंडियन आर्मी नाम के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, कोविड के रोकथाम को लेकर उपायों के कारण भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। जब पूर्वी लद्दाख में हमारी सीमाओं पर संकट विकसित हुआ तो बल संरक्षण के हमारे निर्णय से हमें फायदा हुआ, क्योंकि हम परिचालन की तैयारियों को लेकर बेहतर स्थिति में थे। सेना प्रमुख ने कहा कि जैसे ही उत्तरी सीमाओं पर स्थिति खराब हुई जवान मौके पर पहुंच गए। उन्हें अपने लीडर्स पर पूरा भरोसा था। वे अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सभी चुनौतियों और कठिनाइयों को पार करते हुए काम करने के लिए तैयार थे। यह सब उपलब्ध संसाधनों के कारण हुआ। यह इसलिए संभव हमारे पास पहले से किसी भी परिस्थिति और संभावित विकल्पों को लेकर हमने तैयारी की थी।

जनरल नरवणे ने कहा कि बल संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि हम केवल अपना ख्याल रख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को नागरिकों की सेना होने पर गर्व है, जो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी ओर से हमने इस चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयासों में सक्रिय योगदान दिया है। हम रिकार्ड समय सीमा में देश के कोने-कोने में विभिन्न स्थानों पर क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल बनाने का काम किया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे और आक्सीजन आपूर्ति को मजबूत करने को समग्र राष्ट्रीय प्रयास में एकीकृत किया गया था।

अमेजन के कथित घूसखोरी और 15000 करोड़ रुपये की ड्रग्स तस्करी पर कांग्रेस हमलावर, केंद्र सरकार से पूछे कई सवाल

नई दिल्ली । कांग्रेस ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद किये जाने और ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन से जुड़े कथित रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने कहा कि इन मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों का एक आयोग गठित किया जाना चाहिए.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन मामलों पर देश को जवाब देना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर विषय हैं. उन्होंने सरकार पर उस वक्त निशाना साधा है, जब अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 15000 करोड़ रुपये है. इस बंदरगाह के परिचालन का स्वामित्व अडाणी समूह के पास है.

अडाणी समूह के एक प्रवक्ता ने इस घटनाक्रम पर मंगलवार को कहा था कि बदंरगाहों के परिचालन में परिचालक कंपनियों की भूमिका सीमित होती है तथा कंटेनरों की छानबीन एवं जब्ती का काम सरकारी एजेंसियां ही करती हैं, ऐसे में यह समूह आशा करता है कि सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे 'दुष्प्रचार' पर विराम लगेगा. इस मामले पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

हेरोइन जब्त किये जाने और अमेजन से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, 'दो सनसनीखेज खुलासों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की 'सुपारी' ले रखी है. यही इनका 'खाएंगे, खिलाएंगे और लुटाएंगे' मॉडल है. सुरजेवाला ने सवाल किया, 'क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों का आयोग बनाकर नहीं होनी चाहिए?' कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा, '3000 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी ड्रग तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है. यह कोई पहली बार नहीं है कि इस बंदरगाह के माध्यम से ड्रग्स लायी गयी हो. आज के समाचार पत्रों के मुताबिक, अडाणी मुंद्रा बंदरगाह से जून, 2021 में इसी प्रकार 25,000 किलोग्राम हेरोइन ड्रग, 'सेमीकट टेलकम पाउडर ब्लॉक्स' के नाम पर लायी गयी थी.'

उन्होंने दावा किया, 'हेरोइन की पुरानी खेप बाजार में पहुंच चुकी होगी और हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे की आग में झोंक रही है. यह भी याद रहे कि जुलाई, 2021 में दिल्ली पुलिस ने भी 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की 354 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी की थी. मई महीने में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी.'

सुरजेवाला ने सवाल किया, 'क्या यह सीधे-सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड़यंत्र नहीं? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि इन सारे ड्रग्स के तार तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं.' उन्होंने यह भी पूछा, 'क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश का और सरकारी एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है? अडाणी मुंद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की गई?

अमेजन से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए सुरजेवाला ने दावा किया, 'विदेशी ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने पिछले दो साल में भारत में कानूनी शुल्क के नाम पर 8,546 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

अफगानिस्तानः संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना चाहता है तालिबान, महासचिव को चिट्ठी लिखकर की यह मांग

न्यूयॉर्क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने के लिए एक पत्र लिखा है। इसमें तालिबान ने कहा है कि उसने अपने दोहा स्थित प्रवक्ता सुहैल शाहीन को अफगानिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र के लिए राजदूत के रूप में नामित किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिख उठाई ये मांग

तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिख इस संबंध में अनुरोध किया है। मुत्ताकी ने सोमवार को समाप्त होने वाली महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बोलने देने के लिए कहा।

गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने मुत्ताकी के पत्र की पुष्टि की है। प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अफगानिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में जगह के लिए नौ सदस्यीय क्रेडेंशियल कमेटी को अनुरोध किया गया है। इन सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि तालिबान की इस हफ्ते समिति के साथ बैठक होने की संभावना नहीं है। इसलिए तालिबान के प्रतिनिधि का संबोधन मुश्किल लग रहा है।

अंतरात्मा जागृति अभियानःस्पेन में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, पर डॉक्टरों का इनकार; बोले- जीना या मरना हम तय नहीं करते

मैड्रिड। स्पेन में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार प्राप्त है। कई महिलाएं गर्भपात कराती भी हैं। लेकिन कई ऐसी महिला डॉक्टर भी हैं, जो गर्भपात करने से साफ इनकार भी करती हैं। ऐसी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि वे महिलाओं के गर्भपात करने के अधिकार का सम्मान करती हैं। उनका कहना है कि कोई भी महिला वो फैसला कर सकती है जो उसके लिए बेहतर और सही हो। साथ ही महिला डॉक्टरों का भी ये अधिकार है कि वो गर्भपात करने से इनकार कर दे। स्पेन के सरागोजा शहर की महिला डॉक्टर मर्सेडीज सोबरीवेला का कहना है कि वो गर्भपात का ऑपरेशन नहीं करती हैं। डॉ. सोबरीवेला का कहना है कि हम लोग डॉक्टर हैं। हम लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी मे मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराते हैं।

गर्भपात जीने के अधिकार के खिलाफ

हम बतौर डॉक्टर ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि किसको जीना है और किसको मरना है। स्पेन में गर्भपात के विरोध में अंतरात्मा जागृति का अभियान चल रहा है। इसके समर्थकों का कहना है कि गर्भपात जीने के अधिकार के विरुद्ध है। कई महिला डॉक्टर इस अभियान के समर्थन में हैं। कुछ महिला डॉक्टर गर्भपात ऑपरेशन नहीं करती हैं।

दुनिया के कई देशों में गर्भपात को लेकर बहस छिड़ी

दुनिया के कई देशों में गर्भपात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका के राज्य टेक्सास, मेक्सिको, अर्जेन्टीना, आयरलैंड, पोलैंड ऐसे कुछ देश हैं जहां गर्भपात के समर्थन और विरोध में लगातार प्रदर्शन चलते रहते हैं। अंतरात्मा जागृति अभियान के समर्थन के कारण कई महिला डॉक्टर गर्भपात से इनकार कर रही हैं।

अफगानिस्तान : इस साल छह लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर, बढ़ी बेरोजगारी कमाई नहीं

काबुल। अफगानिस्तान में इस साल हिंसा के चलते 6.35 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इनमें 12,000 से ज्यादा को अकेले पंजशीर प्रांत से काबुल का रुख करना पड़ा। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने बताया है कि विश्व संगठन और उसके सहयोगियों ने 2021 की पहली छमाही में ऐसे 80 लाख लोगों तक सहायता पहुंचाई है। काबुल में लगभग 1,300 विस्थापित लोगों को सहायता मिलने वाली है।

बढ़ी बेरोजगारी, रोजाना 10 रुपये भी कमाई नहीं

अफगानिस्तान में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपनी कार को टैक्सी बनाने से लेकर सड़कों पर सामान बेचने को मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद रोज 10 रुपये तक भी कमाई नहीं हो पा रही है। सैन्य संस्था में काम कर चुके अकरमुद्दीन ने बताया, उन्हें सात महीनों से वेतन नहीं मिला है। मैं किराए के मकान में रहता हूं, जिसका किराया और बिजली खर्च सात हजार रुपये हैं। लेकिन इन दिनों 10 रुपये भी दैनिक आमदनी नहीं रही। ऐसे में गुजर-बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। पेशे से शिक्षक मोहम्मद नासिर ने बताया, उनके परिवार में नौ सदस्य हैं पर कमाने वाले वह अकेले ही हैं। पहले दस हजार रुपये मासिक तक खर्च कर लेता था लेकिन अब तो घर-परिवार का खर्च चलाने के लिए रुपये तक नहीं बचे हैं।

कनाडा चुनावों में भारतीय मूल के लोगों का जलवाःरक्षा मंत्री हरजीत सज्जन समेत 17 नेता जीते; जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में वापसी तय, पीएम मोदी ने बधाई दी

ओटावा। कनाडा के संसदीय चुनाव में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नेता जगमीत सिंह और रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन समेत 17 भारतीय-कनाडाई लोगों ने जीत हासिल की। लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से सत्ता में वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ट्रूडो को बधाई दी। पीएम ने लिखा, चुनावों में जीत के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बधाई। मैं भारत-कनाडा संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग के लिए साथ मिलकर काम जारी रखने का इच्छुक हूं।

जगमीत सिंह बोले- न्यू डेमोक्रेट्स पर भरोसा कर सकते हैं

ट्रूडो को बधाई देते हुए जगमीत सिंह ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ते रहेंगे कि सुपर अमीर अपने हिस्से का भुगतान करें। जगमीत सिंह बर्नाबी साउथ से विजयी हुए। वह करीब 40त्न वोट शेयर से जीते। उन्होंने कहा, ÷मैं कहना चाहता हूं कि कनाडाई जानते हैं कि आप अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए

न्यू डेमोक्रेट्स पर भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि हमने महामारी में आपके लिए लड़ाई लड़ी। जब लोग कठिन समय में संघर्ष कर रहे थे, जब लोग अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे। हम थे वहां पर खड़े रहे।

मंत्री रहे तीन भारतीय-कनाडाई लीडर जीते

भंग कैबिनेट में सभी तीन भारतीय-कनाडाई मंत्रियों (हरजीत सज्जन, अनीता आनंद और बर्दिश चागर) ने भी जीत हासिल की है। रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन करीब 49फीसदी वोट शेयर के साथ वैंकूवर-साउथ से फिर से चुने गए। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा समुदाय मुझे जानता है। जब हम 10, 15, 20, 30 साल पहले हुई चीजों के बारे में बात करते हैं, तो जाहिर है कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब आगे आने का विश्वास रखते हुए और महिलाएं आगे आ रही हैं।

लिबरल नेता अनीता आनंद को वॉलंटियर्स धन्यवाद दियाः लिबरल नेता अनीता आनंद को करीब 46फीसदी वोट शेयर के साथ ओकविल से विजेता घोषित किया गया। आनंद कोरोना वायरस के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान की मंत्री हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं बस खुश हूं। उन्होंने वॉलंटियर्स को धन्यवाद दिया, जिन्होंने एक टीम के रूप में लगातार पांच सप्ताह तक कड़ी मेहनत की।

यूएनजीए में बाइडेन का संबोधनःचीन का जिक्र कर कहा- अमेरिका नया कोल्ड वॉर नहीं चाहता

आतंकवाद का सहारा लेने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन

न्यूयार्क। चीन से तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम एक नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं, जहां पर दुनिया का बंटवारा हो जाए। अमेरिकी उन सभी देशों के साथ काम करने को तैयार है, जो शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी अपनी असफलताओं के परिणाम भुगत चुके हैं।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा है कि अमेरिका अब वही देश नहीं है, जिस पर 20 साल पहले 9/11 को हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि आज हम पहले से और बेहतर और मजबूत हुए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग अमेरिका के खिलाफ

आतंक का सहारा लेंगे वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहेगा।

अफगानिस्तान पर भी बोलेः बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना की वापसी और वहां के हालात को लेकर भी अपनी बात रखी। बाइडेन ने कहा- हम आतंकवाद के कड़वे दंश को जानते हैं। पिछले महीने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले में हमने अपने 13 सैनिकों और कई अफगान नागरिकों को खो दिया। सैन्य शक्ति हमारी अंतिम उपाय का साधन होना चाहिए, न कि पहली।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। हमने अफगानिस्तान में 20 वर्षों का संघर्ष खत्म किया और युद्ध खत्म करने के बाद हमने कूटनीति के दरवाजे खोल रहे हैं। हमारी सुरक्षा, समृद्धि, स्वतंत्रता आपस में जुड़ी हुई है और हमें पहले की तरह दुनिया की सभी चुनौतियों के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाः भूकंप के झटकों से कांपा मेलबर्न, इमारतों को हुआ नुकसान, दहशत में घर से बाहर भागे लोग

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बुधवार सुबह शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के कारण मेलबर्न शहर की कई इमारतों को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि कई घरों की दीवारें टूट गईं और लोग दहशत में घर से बाहर निकल आए। वैज्ञानिकों के मुताबिक, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि उत्तर-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर में झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि भूकंप से किसी गंभीर नुकसान की सूचना नहीं मिली है और न ही किसी के हताहत होने खबर है। बता दें, अभी तक ऑस्ट्रेलिया के ब्रूम में 2019 में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, इसके झटके 210 किलोमीटर तक महसूस किए गए थे।

महामारी से मुकाबला : अमेरिका में 12-17 साल तक के 56त्न बच्चों को टीके की पहली डोज लगी

लंदन। अमेरिका में कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट घातक असर दिखा रहा है। लेकिन स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थान खुलने के बाद बाइडेन सरकार ने बच्चों को महामारी से सुरक्षा कवच मुहैया कराने का युद्धस्तर पर अभियान भी छेड़ा हुआ है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार अमेरिका में अब तक 12 से 17 वर्ष के लगभग 56 फीसदी बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 45 फीसदी बच्चों को दूसरी डोज लग चुकी है।

सरकार ने अभिभावकों में बच्चों को वैक्सीन लगवाने को लेकर झिझक को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान भी छेड़ा है। अमेरिका दुनिया में बच्चों के टीके को मंजूरी देने वाले पहला देश था। मई में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को टीके लगने शुरू हुए। उधर, अमेरिका में अब तक कोरोना से 675722 लोगों की मौत हो चुकी है। 1918 के फ्लू से अमेरिका में 675000

की मौत हुई थी।

कुछ अभिभावकों में टीके की झिझक भीः सर्वे

काइजर फैमिली सर्वे के अनुसार 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20 फीसदी अभिभावकों में बच्चों को टीका लगवाने की झिझक भी है। टेक्सास की रेने कहती हैं कि वो बच्चों को कोरोना पूर्व का सामान्य जीवन जीना देखना चाहती हैं लेकिन बच्चों में साइड इफेक्ट का खतरा रहता है।

6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों का डेटा जल्द

फाइजर का कहना है कि छह माह से 5 वर्ष तक के बच्चों पर उसकी वैक्सीन का डेटा जल्द सामने आने वाला है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरिया का कहना है कि परीक्षणों के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। उम्मीद है कि परीक्षण के अंतिम परिणाम भी बेहतर ही होंगे।

5 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों में बढ़ जाती है इम्युनिटी

फाइजर के अनुसार 5-11 वर्ष तक के बच्चों में कोरोना के प्रति इम्युनिटी में उसकी वैक्सीन कारगर रही है। टीके के बाद बच्चों में प्रतिरोध क्षमता में 66 फीसदी से अधिक विकास देखा गया है। कंपनी जल्द ही वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दवा नियामक को आवेदन करेगी।

महामारी की उत्पत्तिः चीन में मिले 142 नए कोरोना वायरसों से कोविड-19 विवाद में जुड़ेगा नया पहलू?

बीजिंग। चीन के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ से फैलने वाले 142 नए कोरोना वायरसों का पता लगाया है। ये वायरस सार्स रोग फैलाने में सक्षम हैं। लेकिन इन वैज्ञानिकों का कहना है कि नए वायरसों का कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक कोविड-19 महामारी फैलने के बाद पहली बार चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरसों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी जारी की है। इस बारे में एक अनुसंधान पत्र इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोजन रिसर्च स्वेयर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने 4,700 से ज्यादा चमगादड़ों से इन वायरसों के सैंपल हासिल किए। ये काम जनवरी 2020 के बाद से किया गया है। उसके पहले 2016 से इसी इंस्टीट्यूट में हजारों दूसरे प्रकार के कोरोना वायरसों का अध्ययन किया गया है। कोविड-19 का स्रोत भी चमगादड़ों को माना गया था। उसके बाद से इस

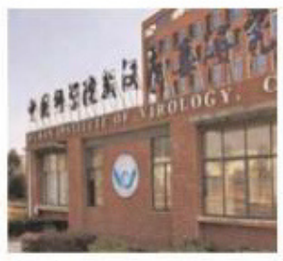

क्षेत्र में व्यापक पड़ताल शुरू की गई। इसमें ऐसे तमाम वायरसों के कोविड-19 वायरस से संभावित संबंधों का अध्ययन किया गया।

कोविड-19 पहली बार चीन के वुहान शहर में 2019 के आखिरी महीनों में सामने आया था। उसके बाद वह दुनियाभर में फैल गया। कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति संबंधी जांच के लिए चीन गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल में शामिल विशेषज्ञ पीटर डेस्जाक ने हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि महामारी फैलने के बाद पहली बार चीनी वैज्ञानिकों की तरफ से सार्स से संबंधित कोरोना वायरस के बारे में इतनी जानकारी दी गई है।

विशेषज्ञों के मुताबिक ताजा रिसर्च पेपर में जो जानकारी दी गई है, वह चीन में पहले निकाले गए कई निष्कर्षों का खंडन करती है। पहले कहा गया था कि सार्स-कोविड-2 के करीबी कोरोना वायरस चीन के चमगादड़ों में दुर्लभ हैं। लेकिन अब सामने आया है कि वहां के चमगादड़ों में ऐसे वायरस बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। पहले चीनी विशेषज्ञों ने कहा था कि सार्स-कोविड-2 जैसे कोरोना वायरस की मौजूदगी के लिए चीन के पड़ोसी देशों में अनुकूल माहौल है। लेकिन अब सामने आया है कि ऐसा वातावरण चीन में भी है।

पाकिस्तान : भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने मंगलवार को एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में एक करोड़ अमेरिकी डॉलर की वसूली के लिए पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की।

नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने कहा कि उसने शरीफ से वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। शरीफ को एवनफील्ड अपार्टमेंट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था। उन पर दस साल की कैद की सजा तथा अस्सी लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था।

यह मामला लंदन के एवेनफील्ड हाउस में शरीफ परिवार के अपार्टमेंट के मालिकाना हक से जुड़ा है। वसूली के उद्देश्य के लिए, (एनएबी) लाहौर ने लाहौर और शेखूपुरा क्षेत्र के उपायुक्तों को नवाज शरीफ के स्वामित्व वाली सभी मौजूदा संपत्तियों को बेचने के लिए लिखा है। एनएबी के अनुसार, 71 वर्षीय शरीफ के पास लाहौर में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमि है,

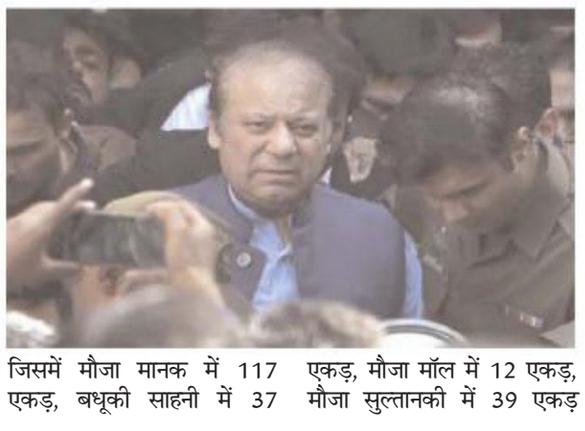

जिसमें मौजा मानक में 117 एकड़, बधूकी साहनी में 37 एकड़, मौजा मॉल में 12 एकड़, मौजा सुल्तानकी में 39 एकड़ और लाहौर के अपर मॉल में एक बंगला शामिल है। इसमें कहा गया है, अगर सभी बिकी हुई संपत्तियों से वसूल की गई राशि जुर्माने की राशि को कवर नहीं करती है, तो एनएबी नवाज शरीफ की किसी भी अन्य मौजूदा संपत्तियों के लिए फिर से नए सिरे से संपत्ति को अधिकृत करेगा। एनएबी ने कहा, पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है कि भ्रष्टाचार के संदर्भ में किसी पूर्व प्रधानमंत्री से इतनी बड़ी राशि वसूल की गई है। एवेनफील्ड मामले में सह-आरोपी और शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी और उन पर 20 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। मरियम नवाज इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। हालांकि, पीएमएल-एन ने एनएबी के कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एनएबी के अध्यक्ष जावेद इकबाल द्वारा अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए एक निराशाजनक याचिका थी जो अगले महीने की शुरुआत में समाप्त होने जा रही है।

ईशनिंदा के नाम पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से बर्बरता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हो रहा उल्लंघन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में दर्ज ईशनिंदा के बढ़ते मामले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बार-बार इस प्रथा विरोध किया है और यूरोपीय संघ सहित विश्व निकायों से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है। ईशनिंदा ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों का जीवन बर्बाद कर दिया है। अधिकार समूहों की कई रिपोर्टों के अनुसार, 1987 से आज तक पाकिस्तान ने लगभग 1600 ईशनिंदा मामले दर्ज किए हैं, जो हिंदुओं, ईसाइयों, शिया और अहमदिया मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में ईशनिंदा के मामले अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। मुल्तान के बहाउद्दीन जकारिया विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता जुनैद हफीज पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था, जो उन्होंने कभी नहीं किया। ईशनिंदा के आरोप में वजीह-उल-हसन को 18 सालों तक जेल में रहाना पड़ा था, जो सितंबर 2019 में निर्दोष साबित हुआ था। पाकिस्तान में चरमपंथी समूहों द्वारा अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ ईशनिंदा का हमेशा दुरुपयोग किया जाता रहा है।

तालिबान राजः ट्रंप की पूर्व अधिकारी बोलीं- पाक के बजाय भारत की मदद ले अमेरिका

वाशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंक-निरोधी सहायता के लिए अमेरिका को भारत के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका को पाकिस्तान पर निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 सितंबर से शुरू दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के पहले यह बयान आया है।

ट्रंप प्रशासन की पूर्व अधिकारी लीजा कर्टिस ने कहा है कि पाकिस्तान को अब दंड देने में देरी हो गई है। सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी थिंक टैंक में हिंद-प्रशांत सुरक्षा कार्यक्रम की निदेशक कर्टिस ने एक पत्रिका में लिखा है कि 2001 से लेकर अब तक कोई भी अमेरिकी प्रशासन अपने क्षेत्र में तालिबान के विरुद्ध अभियान चलाने को लेकर पाकिस्तान को सहमत नहीं कर पाया है।

भारत को रोकने के लिए हक्कानी नेटवर्क पर निर्भर है पाकिस्तान

लिजा कर्टिस ने पत्रिका 'फोरेन अफेयर्स' में लिखा कि 2001 के बाद से अमेरिका का कोई प्रशासन पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में तालिबान

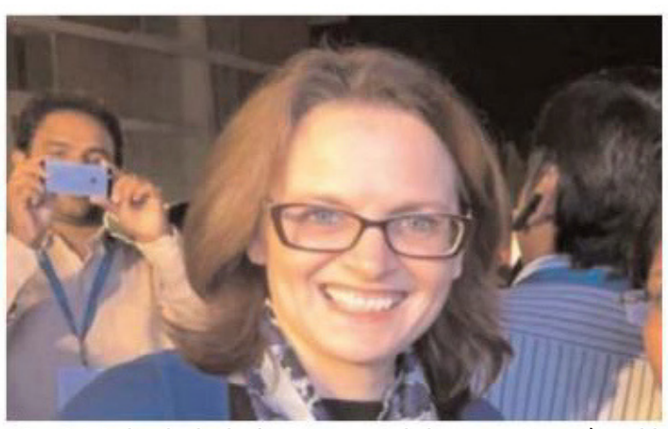

की गतिविधियों को रोकने के लिए समझाने में सफल नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा, आईएसआईएस-के जैसे अन्य आतंकी गुटों को निशाना बनाते समय

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंक-निरोधी सहायता के लिए अमेरिका को भारत के साथ काम करना चाहिए।

वाशिंगटन के लिए इस्लामाबाद के साथ काम करना संभव हो सकता है, लेकिन पाक खुफिया एजेंसी अलकायदा से जुड़े हक्कानी नेटवर्क को कभी निशाना नहीं बनाएगी। पाक सेना और आईएसआई भारत को अफगानिस्तान में पैर जमाने से रोकने के लिए हक्कानी नेटवर्क पर निर्भर हैं।

अलकायदा व आईएस की मौजूदगी से झाड़ा पल्ला

तालिबान ने अलकायदा और आईएस के आतंकवादियों की अफगानिस्तान में मौजूदगी के आरोपों से साफ इनकार किया है। यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब आईएस ने जलालाबाद सीरियल धमाकों की जिम्मेदारी ले ली है। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पत्रकारों से कहा, आईएस बिना सामने आए कुछ कायराना हमले करता है। इसकी इराक और सीरिया में मौजूदगी है। लेकिन हमारे पास ऐसे संगठनों के देश में सक्रिय होने के कोई सबूत नहीं हैं। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अफगानिस्तान से किसी भी देश को खतरा नहीं होगा। एजेंसी

धमाकों के बाद 40 लोग गिरफ्तार :

नंगरहार की राजधानी जलालाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों को लेकर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरिआना न्यूज ने नंगरहार प्रांत के खुफिया निदेशालय प्रमुख बशीर के हवाले से यह जानकारी दी है।

संक्षिप्त खबर

सत्येंद्र जैन बोले- केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी पर की राजनीति, मौतों को छिपाने का किया प्रयास

नई दिल्ली । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान यहां ऑक्सीजन की कमी पर उसने जमकर राजनीति की. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समिति गठित किए जाने को रोकने का प्रयास कर रही है. उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही. एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि कथित चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए आप सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन में उसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है.

जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जून में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल थे और फाइल को मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा गया. उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र ने उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया. जैन ने आरोप लगाए, ''केंद्र ने ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर भी राजनीति की और संसद में भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की कोई खबर नहीं है.'' दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने ''मौतों को छिपाने का प्रयास कर गलत काम किया है'' जो जीवन रक्षक गैस की कमी के कारण हुई होंगी. उन्होंने कहा कि अदालत ने अब समिति के गठन के लिए रास्ता साफ कर दिया है. जैन ने संवाददाताओं से कहा, ''इस समिति का काम ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत होने का दावा किए जाने की जांच करना है, चाहे वह मौत घर में हुई हो या अस्पताल में. समिति जांच करेगी और पांच लाख रुपये तक के मुआवजा की अनुशंसा करेगी. यह किसी चिकित्सीय लापरवाही की जांच नहीं करेगी, जो चिकित्सा परिषद का काम है.''

गाली गलौज का बदला लेने के लिए युवक पर हुआ जानलेवा हमला

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट जिला अंतर्गत वेलकम इलाके में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. यह हमला गाली गलौज का बदला लेने के लिए किया गया. जानलेवा हमले में घायल शख्स शाहरूख को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक हमलावर युवक आरोपी की पहचान कर ली गई है. घटना को लेकर पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक शाहरूख परिवार के साथ वेलकम में रहता है और उनका जींस का कारोबार है. रात के समय किसी काम से कांटे वाली गली से होते हुए जनता कालोनी जा रहे थे. गली में उन्हें उनका परिचित मिल गया, उसने उनका रास्ता रोका और कहा कि एक दिन पहले तुने मुझे गाली कैसे दी थी. पीड़ित ने गाली देने से इन्कार किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी.

गाली गलौज का पीड़ित ने विरोध किया तो चाकू निकाल कर उसकी जांघ पर मार दिया, पीड़ित दर्द से चिल्लाया और वहां से भागकर अपने घर जाने लगे, घर से कुछ दूर पहले बेहोश होकर गली में गिर गया. परिवार ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया.

भजनपुरा इलाके में मजदूर पर गिरा किचन की दीवार का हिस्सा, हालत गंभीर

नई दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक दीवार का बड़ा हिस्सा गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल मजदूर को नजदीक के सरकारी अस्पताल जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घायल मजदूर की पहचान ब्रिजलाल के रूप में की गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. जानकारी के मुताबिक घायल मजदूर मूल रूप से उत्तर प्रदेश चित्रकूट का रहने वाला है. वह गांवड़ी इलाके में किराए पर रहता है और मजदूरी करता है. घटना की जानकारी देते हुए ब्रिजलाल के भांजे रामकुमार ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से अपने मामा के साथ भजनपुरा इलाके में एक मकान की मरम्मत का कार्य कर रहे थे. सुबह बिजलाल अकेले काम पर पहुंच गए थे और एक रसोई घर की दीवार को तोड़ने लगे. इस दौरान दीवार तोड़ते वक्त अचानक एक हिस्सा उनके ऊपर गिर गया. इस हिस्सा के गिरने की वजह से मजदूर के सिर और बाकी हिस्सों में गंभीर चोटें आई है. हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूर को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

मनजीत सिंह जीके ने एसजीपीसी अध्यक्ष जागीर कौर का मांगा इस्तीफा, लगाया गंभीर आरोप

नई दिल्ली । मनजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद अब जग आसरा गुरु ओट (जागो) के नेता मनजीत सिंह जीके ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि एसजीपीसी ने गलत तरीके से सिरसा को डीएसजीएमसी में अपना नामित सदस्य मनोनित किया है. इसके लिए एसजीपीसी की अध्यक्ष जागीर कौर जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें एवं पूरी कार्यकारिणी को इस्तीफा देना चाहिए. इसके लिए वह अदालत जाएंगे. प्रेस वार्ता में मनजीत सिंह जीके ने कहा कि 25 अगस्त को चुनाव परिणाम आने के कुछ देर बाद ही शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सिरसा को डीएसजीएमसी का अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी. उनके इशारे पर एसजीपीसी द्वारा अपना सदस्य मनोनित करने का पत्र भी जारी हो गया. उस पत्र में 23 अगस्त को हुई एसजीपीसी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई है, जबकि चुनाव परिणाम 25 अगस्त को आया है. एसजीपीसी के दो सदस्यों ने अदालत में भी कहा है कि बैठक में इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि एसजीपीसी अध्यक्ष व कार्यकारिणी के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी की शिकायत करेंगे. उन्होंने कहा कि शिअद बादल के दस अन्य सदस्यों के खिलाफ पंजाबी का ज्ञान नहीं होने की शिकायत अदालत में की गई है. उन्होंने गुरुद्वारा चुनाव निदेशक से डीएसजीएमसी के चुने हुए सभी 46 सदस्यों का पंजाबी का टेस्ट कराने की मांग की. डीएसजीएमसी के पूर्व सदस्य कुलवंत सिंह बाठ ने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के व्यक्तिगत अदालती मामले में गुरु के गोलक से पैसे खर्च कर वकील रखे जा रहे हैं। जागो के मुख्य महासचिव परमिंदर पाल सिंह ने सिरसा को अपनी बीए (पंजाबी आनर्स) की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की।

सिरसा डिग्री दिखा दें तो डीएसजीएमसी से इस्तीफा दे दूंगा: सरना- शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (सरना) के महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा को अयोग्य घोषित होने से पूरे विश्व में डीएसजीएमसी की बदनामी हो रही है. यह संदेश गया कि सिखों के प्रमुख धार्मिक संस्था के प्रमुख को पंजाबी का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष को न तो पंजाबी और सिख इतिहास की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यदि सिरसा बीए (पंजाबी आनर्स) की डिग्री दिखा देंगे तो वह उनके खिलाफ किए हुए मुकदमें वापस लेने के साथ ही कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे।

कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर का ट्रायल पूरा, 1 अक्टूबर से पूरी क्षमता से काम करना करेगा शुरू

नई दिल्ली । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर का ट्रायल पूरा हो चुका है और यह एक अक्टूबर से पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके कामकाज की निगरानी के लिए आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी-दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया है।एक अधिकारी ने कहा कि टीम में आईआईटी-बॉम्बे के पांच और आईआईटी-दिल्ली के एक विशेषज्ञ होंगे। स्मॉग टॉवर में मिनेसोटा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित 40 पंखे और 10,000 फिल्टर हैं। विशेषज्ञ स्मॉग टॉवर के कामकाज का विश्लेषण करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या यह प्रभावी है। यदि यह सफल होता है, तो दिल्ली भर में ऐसे कई स्मॉग टॉवर लगाए जा सकते हैं। यदि नहीं, तो हम किसी अन्य तकनीक पर काम करेंगे। बता दें कि 24 मीटर से अधिक ऊंचे स्मॉग टॉवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त को किया था।

चांदनी चौक में फुटपाथ से लेकर सड़क तक पर अवैध रेहड़ी-पटरी वालों के साथ बेघर और भिखारियों की भी बढ़ गई संख्या

नई दिल्ली । ज्यादा दिन नहीं बीते, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकसित मुख्य मार्ग के उद्घाटन अवसर को संबोधित करते हुए कहा था कि यह क्षेत्र दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार हो गया है। जो भी पर्यटक दिल्ली आएंगे, वह चांदनी चौक जरूर आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की इन उम्मीदों और सपनों को सिविक एजेंसियों की लापरवाही पलीता लगा रही है। स्थित यह है कि चांदनी चौक मुख्य मार्ग के प्रवेश द्वार पर भारी संख्या में रेहड़ी-पटरी वालों का कब्जा हो गया है। यह स्थित लाल जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर पहुंचते-पहुंचते और बिगड़ी नजर आ रही है। पूरे मार्ग पर रेहड़ी-पटरी वालों के साथ बेघर और भिखारी बैठे हुए हैं।

यह स्थिति तब है जब चांदनी चौक का यह इलाका रेहड़ी-पटरी वालों से मुक्त घोषित है। आगे फुटपाथ और सड़क पर यह निराश करने वाला दृश्य फतेहपुरी मस्जिद तक मिल जाएगा। वैसे, इस मामले में पहले भी

हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। फिलवक्त मामला नए सिरे से हाई कोर्ट में है।

-डेढ़ किमी सड़क मोटर वाहन मुक्तबता दें कि लालकिला से फतेहपुरी मस्जिद तक करीब डेढ़ किमी सड़क को नए सिरे से मोटर वाहन मुक्त बनाया गया है। दावा तो यह किया गया था कि इसपर सीमित संख्या में हाथ रिक्शे ही चलेंगे, लेकिन इस मार्ग पर मौजूद रिक्शों की संख्या अभी भी सैकड़ों में है। यहां तक की बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं की सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट चलाने के दावे भी धरातल पर नहीं उतरे हैं।

वैसे, रिक्शों और रेहड़ी-पटरी वालों पर लगाम लगाने के लिए वालंटियर्स की तैनाती की गई है, लेकिन वह भी सक्रिय नजर नहीं आते। इससे चांदनी चौक आने वालों को निराशा हो रही है। इंदिरापुरम से खरीदारी करने आई अंकिता खंडेलवाल ने निराशा जताते हुए कहा कि वह यह सोचकर आई थीं कि काफी अच्छा और साफ-सुधरा होगा, लेकिन यहां की स्थिति उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। -फुटपाथ को बिस्तर बना रहे बेघर लोगद बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कूचा महाजनी के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने कहा कि रात में स्थिति और नारकीय हो जाती है। जब सैकड़ों की संख्या में बेघर सड़क और फुटपाथ को बिस्तर बना लेते हैं।

अगर समय रहते लगाम नहीं लगाया गया तो यह रैन बसेरे में तब्दील हो जाएगा। मामला हाई कोर्ट मेंइस संबंध में जब नगर निगम से पक्ष मांगा गया तो एक अधिकारी ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल इस मार्ग पर गलत तरीके से रेहड़ी-पटरी वालों को बैठाने के मामले को हाई कोर्ट में ले गई है, जिसपर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पंजाब के बाद अब दिल्ली में दलितों को लुभाने में जुटी कांग्रेस, 25 सितंबर को अंबेडकर भवन में महापंचायत

नई दिल्ली । दलित समाज से जुड़े मुददों को लेकर प्रदेश कांग्रेस और विभिन्न दलित संगठनों की ओर से शनिवार को अंबेडकर भवन में दलित महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस दिशा में तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। महापंचायत के संयोजक प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयकिशन ने बताया कि इस महापंचायत में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के दलित संगठनों के बुद्धिजीवियों के भी भाग लेने की संभावना है। इसके लिए जगह जगह बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है। जयकिशन ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा लगातार की जा रही दलितों की अनदेखी, उनके अधिकारों में कटौती, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तथा आए दिन दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ महापंचायत करने का फैसला किया गया है। उन्होने यह भी कहा कि दोनों ही सरकारें चुनावों के समय किए गए वायदे पूरा करने में भी असफल रही हैं। उन्होने कहा कि महापंचायत में दलितों के अधिकारों में कटौती, सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव, उनकी पेंशन, बकाया वेतन देने व पक्का करने की मांग, पदोन्नति नही किए जाने तथा उनके अधिकारों के हनन की आवाज उठाई जाएगी।

बता दें कि पंजाब में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए वहां के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित नेता और पार्टी विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। पंजाब में दलितों की आबादी अधिक होने के नाते सभी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर है। इस लिहाज से कांग्रेस का यह फैसला दलितों को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, द इंटरनेशनल वूमैंस इन्सोल्वेंसी एंड रिस्ट्रक्चरिंग कंफडरेशन (आइडब्ल्यूआइआरसी) ने चौथे वूमैन आफ द ईयर इन रिस्ट्रक्चरिंग (डब्ल्यूओवाइआर-एशिया) 2021 से ममता बिनानी को नवाजा है। यह अवार्ड वकील, न्यायाधीश, बैंकर, लेखाकार, प्रबंधक, पुनर्गठन सलाहकार और शिक्षाविद इत्यादि किसी भी पेशेवर के लिए खुला है।

दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन रहेगी पानी की किल्लत, नोट कर लीजिए लिस्ट

नई दिल्ली। पेयजल से जुड़ी योजना पर काम चलने के चलते और भूमिगत जलाशय के प्रस्तावित सफाई कार्य के कारण बृहस्पतिवार को दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र के नजदीक स्थित रेनी वेल से पानी भरने के लिए जो नई जगह बनाई बनाई गई है, वहां बोरवेल बनाने के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इस वजह से ताहिरपुर मुख्य पाइप लाइन से 22 सितंबर को पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस वजह से गमरी गांव, यमुना विहार, भजनपुरा, उत्तरी व पश्चिमी घोंडा, मौजपुर के कई इलाके, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, नंद नगरी, मंडोली, सबोली, हर्ष विहार और इसके आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

वहीं, इसके अलावा भूमिगत जलाशय के सफाई कार्य के कारण 22 सितंबर को ही शालीमार बाग एसी ब्लाक, रोहिणी सेक्टर 21 पाकेट सात में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 23 सितंबर को रोहिणी सेक्टर 23 के पाकेट दो व शालीमार बाग के बीसी ब्लाक में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। लिहाजा जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के मुताबिक पानी भरकर रख लें। पेयजल किल्लत होने लोग जल बोर्ड के केंद्रीय काल सेंटर के नंबर (1916) पर काल कर सकते हैं।

इससे पहले जुलाई महीने में भी पानी की किल्लत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि पानी की कमी के कारण चंद्रावल जलशोधन केंद्र में उत्पादन 90 एमजीडी से घटकर 55, वजीराबाद में 135 से 80 और ओखला में 20 से घटकर 15 एमजीडी रह गया था। दिल्ली सरकार के मुताबिक, हरियाणा से आपूर्ति कम होने की वजह से दिल्ली में पानी का उत्पादन 245 एमजीडी से घटकर 145-150 एमजीडी रह गया था। सरकार के मुताबिक, यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश के बावजूद 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी रोक दिया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली के तीन प्रमुख जल शोधन संयंत्र हैं, जहां पानी का शोधन किया जाता है।

आनलाइन होगी प्रैक्टिकल की पढ़ाई, एनईपी के तहत डीयू स्नातक छात्र पढ़ेंगे छह नए पाठ्यक्रम

नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय बंद है। तृतीय वर्ष के विज्ञान संकाय के छात्रों को प्रयोगशाला और लाइब्रेरी के प्रयोग के लिए कालेज में प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन छात्रों की उपस्थिति बेहद कम हैं। इसे देखते हुए डीयू अब आनलाइन पढ़ाई पर संजीदगी से विचार कर रहा है।

नई शिक्षा नीति में भी आनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया है। इसके मद्देनजर डीयू न केवल पाठ्यक्रमों के वीडियो तैयार कर रहा है बल्कि ई-प्रैक्टिकल का खाका भी तैयार कर लिया गया है। डीयू के विभाग व कालेज में प्रैक्टिकल के वीडियो बनाए जाएंगे। इसे डीयू की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह वीडियो छात्र निश्शुल्क देख सकेंगे।

प्रत्येक अध्याय का वीडियो- डीयू के एक उच्च पदाधिकारी ने बताया कि दिशानिर्देश उन सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिनमें प्रैक्टिकल हैं। दिशानिर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक विभाग यथासंभव वीडियो बनाएंगे। इसके लिए प्रत्येक विभाग में चार-चार सदस्यों की टीम गठित की जाएगी। एक बार वीडियो तैयार हो जाने पर इसे कालेजों से साझा किया जाएगा। कालेज के शिक्षक भी अपने छात्रों के लिए वीडियो बनाएंगे।

डीयू ने बनाई वेबसाइट- वचरुअल लर्निंग एन्वायरमेंट नाम से एक वेबसाइट तैयार की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्तमान वेबसाइट पर इसका लिंक दिया जाएगा। जिस पर क्लिक करते ही यह वेबसाइट खुलेगी। छात्रों को अपने रोल नंबर आदि के जरिए यहां अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद छात्र ई-कंटेट, ई-लैब की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।

कई विभागों और कालेजों के शिक्षक खासे परेशान- दिल्ली विश्वविद्यालय के कई विभागों और कालेजों के शिक्षक खासे परेशान हैं। परेशान हो भी क्यों न, छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं। छात्र दरअसल, फेसबुक, ट्विटर पर वायरल हो चुके एक फर्जी सकरुलर के चलते फोन कर रहे हैं। इस सकरुलर में कहा गया है कि चार अक्टूबर से डीयू के विभागों और कालेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों की आफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होंगी।

डीयू प्रशासन ने बताया कि बड़ी संख्या में छात्र फोन कर कालेज खुलने, आफलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। डीयू ने एक सकरुलर जारी कर कहा है कि चार अक्टूबर से आफलाइन कक्षाओं की सूचना गलत है। डीयू ने इस तरह का कोई सकरुलर जारी नहीं किया है। डीयू ने छात्रों से गुजारिश की कि वे पुष्ट सूचनाओं के लिए डीयू और कालेजों की वेबसाइट ही देखें।

डीयू नई शिक्षा नीति को स्वीकार कर चुका है। अकादमिक और कार्यकारी परिषद की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव भी पास हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत ही पढ़ाई होगी।

एनईपी के तहत स्नातक स्तर पर छह नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। डीयू ने इन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि अकादमिक परिषद ने इन पाठ्यक्रमों पर मुहर लगा दी है। पाठ्यक्रमों के तहत क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, कौन-कौन से अध्याय होंगे, कमेटी इसका चयन कर रिपोर्ट देगी। सदस्य ने बताया कि एथिक्स एंड कल्चर, सोशियल एंड इमोशनल लर्निंग, इनोवेशन, को-करिकुलर, साइंस एंड सोसायटी और आइटी स्किल-डेटा एनालिसिस को शामिल किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में इस बार फिर गहरा सकता है प्रदूषण, पंजाब में पराली के लिए नाकाफी इंतजाम

नई दिल्ली । सितंबर गुजरने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता शुरू हो जाती है. सांसों को घोंटने वाला यह संकट सिर्फ राजधानी दिल्ली को ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों को भी अपनी जद में ले लेता है. हर साल का सबसे बड़ा संकट बन चुके इस प्रदूषण को लेकर पंजाब के खेतों में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है. पिछले साल पंजाब में धान की पराली को खेतों में ही जला देने के मामलों में 44 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. वहीं विशेषज्ञों की मानें तो इस साल पंजाब सरकार की ओर से पराली जलाने पर रोक लगाई गई है लेकिन इंतजाम नाकाफी होने के चलते इस साल भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गहराने की आशंका है.

पंजाब में पराली जलाने के रोकने के इंतजामों को लेकर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव करुनेश गर्ग का कहना है कि राज्य के अधिक प्रभावित गांवों में पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए 8500 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही आग की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. जिनसे डाटा लेकर मोबाइल एप से डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा. वहीं सम्बन्धित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जरूरी हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई हैं कि इन गांवों में विशेष ध्यान दिया जाए, जहां पिछले सीजन के दौरान हर पराली को आग लगाने की 25 से अधिक घटनाएं घटीं थीं.

हर साल सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है.

गर्ग कहते हैं कि नोडल अधिकारी किसानों को पराली जलाने से परहेज करने के प्रति जागरूक करने के अलावा धान की कटाई के बाद के कार्यों पर भी नजर रखेंगे. पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सहकारिता, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, कृषि, बागबानी और भूमि संरक्षण सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी किसान बैठकें, पराली क निपटारे के लिए मशीनों का बंदोबस्त करना, गांवों में प्रचार सामग्री बांटने का काम करेंगे.

पंजाब सरकार के नोडल अधिकारी और कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक मनमोहन कालिया कहते हैं कि धान के बचे हुए हिस्से को खेतों में जलाने से रोकने के लिए सरकार की ओर से काफी व्यवस्थाएं की गई हैं. लेकिन इंतजामों की बात करें तो वे पर्याप्त नहीं हैं. पराली को निपटाने के लिए जितने बजट की मांग की गई थी, केंद्र सरकार की ओर से उसका एक तिहाई ही राज्य को दिया गया है. पिछले तीन वर्षों में पंजाब सरकार ने काफी मेहनत की और किसानों के लिए 76,626 कृषि मशीनें या यंत्र सप्लाई किए. ये मशीनें किसानों को 50 से 80 फीसदी की सब्सिडी पर दी गईं. आज ये स्थिति है कि बड़ी संख्या में किसान ये मशीनें लेने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के पास उनकी मांगें पूरी करने के लिए संसाधन ही नहीं हैं.

कालिया कहते हैं कि इस एक ही समय में फसल की बुवाई और बिजाई का काम होने के चलते निश्चित समय के लिए हर गांव में ज्यादा मशीनों की जरूरत होती है. इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से एक लाख और मशीनों की मांग की थी, ताकि किसानों की मांग के अनुरूप सप्लाई हो सके. लेकिन केंद्र की ओर से सिर्फ एक तिहाई बजट मिलने के कारण इस साल एक लाख की मांग की जगह सिर्फ 31 हजार मशीनें ही और उपलब्ध कराई जा सकेंगी. मशीनें लेने आ रहे सभी लोगों को इस बार मशीनें नहीं मिल सकेंगी.

किसानों का विरोध प्रदर्शन भी प्रदूषण की वजह- कृषि विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश कुशवाह का कहना है कि जहां तक पराली जलाने की बात है, तो पिछले साल कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने खेतों में जगह-जगह पराली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था. वहीं इस साल की बात करें तो किसान अभी भी दिल्ली-एनसीआर में धरने पर बैठे हुए हैं. किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं ऐसे में आशंका है कि विरोध के चलते पहले की तरह किसान खेतों में पराली जलाने की प्रक्रिया दोहरा सकते हैं और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर बढ़ सकता है.

इस बारे में कालिया कहते हैं कि जैसा कि कई रिपोर्ट में भी कहा गया था कि पंजाब में पिछले साल 44 फीसदी ज्यादा पराली जलाई गई, लेकिन अगर मात्रा को देखें तो पिछले साल पराली जलाने की मात्रा कम थी हालांकि विरोध के चलते स्थानों की संख्या ज्यादा थी. इस बार किसानों से ऐसा न करने की अपील की जा रही है.

पिछले साल ये जिले थे हॉटस्पॉट

पंजाब राज्य के पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फिरोजपुर, श्रीमुक्तसर साहिब, तरन तारन, मोगा और मानसा को सबसे अधिक प्रभाविज जिलों की श्रेणी में रखा गया है. अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों में पिछले सीजन में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई थीं. पिछले साल भी पराली जलाने पर रोक थी और किसानों से मशीनों का इस्तेमाल करने की अपील की गई थी, लेकिन कई जिलों में धान की पराली को आग लगने की 4000 से अधिक घटनाएं तक दर्ज की गई थीं. लिहाजा इस बार पराली पर कितना नियंत्रण हो पाता है यह देखना होगा.

हिंदू शरणार्थियों को बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर डीएचसी ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ टाटा पावर से भी मांगा जवाब

नई दिल्ली । पाकिस्तान के लगभग 800 हिंदू शरणार्थियों को बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ टाटा पावर से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। 200 परिवारों के 800 लोग दिल्ली जल बोर्ड मैदान में रह रहे हैं। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक प्रवासियों के लिए काम करने वाले याचिकाकर्ता हरिओम ने कहा कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को उम्मीद थी कि भारत आने से उनके बच्चों को उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य मिलेगा, लेकिन झुग्गी में बिजली की सुविधा भी नहीं है।

अधिवक्ता समीक्षा मित्तल व आकाश वाजपेयी के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सभी स्कूल आनलाइन हो गए हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय है।

उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आयकर विभाग से कहा कि आनलाइन समाचार पोर्टल न्यूजलांड्री से जब्त की गई सामग्री की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए बाध्य है। वहीं, आयकर विभाग की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने भी हाई कोर्ट को आश्वस्त किया कि सर्वे के दौरान जब्त की सामग्री का इस्तेमाल कानून के हिसाब से किया जाएगा। संभव है कि अन्य एजेंसी से इसे साझा किया जाए, लेकिन तीसरे पक्ष को लीक नहीं किया जाएगा।

आयकर विभाग के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए पीठ ने सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी की याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने आयकर विभाग द्वारा कुछ समय पहले किए गए एक सर्वे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज व सामग्री को लीक करने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि आयकर अधिनियम के तहत उन्हें चार नोटिस जारी किए गए थे और दस सितंबर को न्यूज पोर्टल के परिसर में एक सर्वे किया गया था। इसमें मोबाइल फोन, लैपटाप सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए थे।

ऑटो में सवार बुजुर्ग दंपति से हुई लूटपाट, नकदी व सामान लूटकर बदमाश फरार

नई दल्ली. दल्ली पुलस के कोतवाली थाना अंतर्गत इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत से लूटपाट की वारदात को अंजाम दया है. इस घटना को उस समय अंजाम दया गया जब बुजुर्ग दंपत ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे. उस दौरान बदमाशों ने ऑटो के गीता कालोनी फ्लाईओवर से आगे राजघाट की तरफ चलते ही ओवरटेक कया और ऑटो में सवार महला से बैग लूट कर फरार हो गए.

जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग दंपति से लूटे गए बैग में नकदी व अन्य कीमती सामान था. घटना के बाद से बुजुर्ग दंपति बहुत डरी और सहमी हुई है. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. पुलिस आरोपियों की तलाश करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद भी ले रही है.

पुलिस के मुताबिक लीना भाटिया परिवार के साथ आईपी एक्सटेंशन में रहती हैं. इनके परिवार में पति सुरेश के अलावा अन्य सदस्य हैं. लीना का मधु विहार इलाके में अपना कारोबार है. लीना पति व बेटी के साथ खरीदारी करने के लिए अपने घर से चांदनी चोक के लिए निकली थी जैसे ही वह राजघाट यमुना वाले रोड पर पहुंची. रिंग रोड बाईपास से आगे निकलते ही सफेद रंग के बाइक सवार दो युवकों ने इनके ऑटो को ओवरटेक कर रोक लिया.

आरोपी ने चाकू दिखाकर पीड़िता लीना से उनका बैग लूट लिया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.

डीटीसी ने आक्सीजन टैंकर खरीद की वित्तीय मंजूरी का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा, जल्द मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के निर्देश पर आक्सीजन टैंकर खरीदने संबंधी प्रक्रिया में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) सक्रियता से जुटा है। डीटीसी ने आक्सीजन टैंकर खरीद की वित्तीय मंजूरी का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है। दिल्ली को आक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर जल्द मिलने की उम्मीद है। टैंकर खरीद संबंधी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके लिए निविदा में तीन कंपनी शामिल हुई थीं। निविदा का तकनीकी मूल्यांकन हो चुका है। एक कंपनी निविदा संबंधी सभी शर्तों को पूरा कर सकी है, जिसके द्वारा आक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे।

दिल्ली सरकार से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद टैंकर खरीद का आर्डर जारी होगा, जिसके 30 दिन के अंदर टैंकर आना शुरू हो जाएंगे। डीटीसी अलग-अलग टन की क्षमता वाले 15 टैंकर खरीदेगा। इनमें 10, 15 और 20 टन की क्षमता वाले पांच-पांच टैंकर शामिल हैं। एक साल तक टैंकर की आपूर्ति करने वाली कंपनी इनका निश्शुल्क रखरखाव करेगी। क्रायोजेनिक टैंकर में गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में आसानी होगी। इस टैंकर में आक्सीजन लिक्विड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम से लेकर कई दूसरी गैसों को ले जाया जा सकता है।

उधर दिल्ली में एक अक्टूबर से दुकानों पर शराब की किल्लत न हो इसके लिए आबकारी विभाग योजना बनाने में जुट गया है। विभाग ने सभी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स से शराब और बीयर के स्टाक का लेखा-जोखा मांगा है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत एक अक्टूबर से 260 प्राइवेट शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर तक सिर्फ 372 सरकारी शराब की दुकानों पर ही ग्राहक शराब और बीयर खरीद सकेंगे। इसके बाद ये दुकानें भी बंद हो जाएंगी।

वहीं, 17 नवंबर से शराब की नई 849 दुकानें दिल्ली में अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगी। आबकारी विभाग ने सभी होलसेलरों से कहा है कि वे अगले चार महीने का स्टाक वैसे ही मेंटेन करत रहें, जैसे अभी कर रहे हैं। शराब के स्टाक में किसी भी तरह की कमी न करें। विभाग यह सुनिश्चित करने में लगा है कि मांग और आपूर्ति में कितना अंतर रहा।

संपादकीय

काबुली इस्लामी अमीरात के बहाने

काबुल में तालिबानी कब्जे के बाद जिस तरह का विमर्श चल रहा है, वह कई तरह के सरलीकरण का शिकार है। बिना गहराई से जांचे-परखे कुछ चीजें मान ली गई हैं। मसलन, विश्व की एक महाशक्ति अमेरिका तालिबान से हारकर भाग गई, तालिबान के पूर्वज जेहादियों ने पहले दूसरी महाशक्ति सोवियत रूस को भी मार भगाया था या नए तालिबान ज्यादा समझदार हैं और पुरानी गलतियां दोहराने नहीं जा रहे। ऐसी बहुत सारी स्थापनाएं हैं, जो आंशिक रूप से ही सत्य हैं। पहले अफगानिस्तान से दो महाशक्तियों के हारकर भाग जाने को ही ले लें। पहली लड़ाई में, सोवियत रूस के खिलाफ जो मुजाहिदीन लड़े, वे सिर्फ अफगान नहीं थे। सोवियत रूस को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने पूरी मुस्लिम दुनिया से जेहादी इकट्ठे किए थे, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस्लाम का कट्टरपंथी भाष्य तैयार हुआ था, जिसे बाहरी फंडिंग की मदद से पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ाकर खुदकुश हमलावरों की एक पीढ़ी तैयार की गई थी और जिसे पश्चिमी हथियारों की मदद से सोवियत समर्थक शासकों को उखाड़ फेंकने में इस्तेमाल किया गया। इस बार जब मुजाहिदीन तालिबान के नाम से अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, तब समूची दुनिया को यह पता था कि उन्हें पाकिस्तानी सेना की पूरी मदद हासिल है। दुनिया भर से जकात के नाम पर उन्हें आर्थिक मदद मिली।

अमेरिका की हार का मिथक भी गहरी पड़ताल की मांग करता है, खास तौर से उसकी तुलना वियतनाम से अमेरिकी पलायन से तो कतई नहीं की जा सकती। सन 2001 के 9/11 के बाद अमेरिका ने जो युद्ध छेड़ा, उसके दो ही शुरुआती मकसद थे- ओसामा बिन लादेन समेत उस पर हमले के दोषियों को सजा देना और अल-कायदा की क्षमता को नष्ट करना। 2012 में ओसामा को मारकर अमेरिका ने दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए थे, पर वह उस मरीचिका में उलझ गया था, जिसमें पश्चिम अक्सर फंसकर रह जाता है। उसने अफगानिस्तान में यूरोप या अमेरिका के तर्ज का उदार और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाने की कोशिश की, जिसके लिए अफगान समाज सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक रूप से तैयार न था। नतीजा वही निकला, जिसकी उम्मीद थी। साल 2012 में अमेरिका शायद इसलिए नहीं जा सका कि उस पर सोवियत पतन के बाद अफगानिस्तान को मंझधार में छोड़कर चले जाने का आरोप फिर न लगाया जाए, लेकिन इस बार भी खिसियाहट ही उसके हाथ लगी है। इसका एक ही मनोवैज्ञानिक लाभ हुआ कि लोगों को तालिबानी शासन (1996-2001) और अमेरिकी प्रभुत्व वाले समाज में औरतों या अल्पसंख्यकों की स्थिति की तुलना करने का मौका मिला है।

यह सोचना भी सरलीकरण है कि इस बार के तालिबान बदले हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नया नेतृत्व ज्यादा समझदार है, लगभग वैसे ही जैसे, उनके लिए पहले कुछ 'अच्छे' तालिबान हुआ करते थे। वे अगर समझदार हुए हैं, तो सिर्फ अपनी बाह्य संरचना में। अब उनके प्रवक्ता अंग्रेजी में कूटनीतिक रूप से द्विअर्थी बयान देने लगे हैं या उन्हें समझ आ गया है कि यदि साल 2001 में उन्होंने अमेरिकी मांग मानकर ओसामा बिन लादेन को उसके हवाले कर दिया होता, तो पिछले 20 साल उन्हें पहाड़ियों पर लड़ते हुए न बिताने पड़ते और आज भी उनकी हुकूमत होती। पर इससे अधिक कुछ नहीं। आज भी वे पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों से पढ़कर निकले, बर्बर मानसिकता के लोग हैं, जिनकी औरतों, अल्पसंख्यकों या मानवाधिकारों को लेकर सोच पहले जैसी ही पिछड़ी है और सिर्फ दुनिया के सामने उसे पेश करने का तरीका बदला है।

यह सोच मूर्खतापूर्ण होगी कि बगल में घट रहे इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम का भारत पर असर सिर्फ कुछ हजार शरणार्थियों के यहां आगमन या सहायता के नाम पर खर्च किए गए तीन अरब डॉलर पानी में चले जाने भर होगा। हम लाख इनकार करें, इसका पूरा असर हमारे देश में रह रहे दो बड़े धर्मावलंबियें- हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ेगा। यह एक कटु सच्चाई है कि पिछले कुछ दशक देश में कट्टर हिंदुत्व के उभार के रहे हैं। इस उभार से जो मानसिकता बनी है, वह एक स्टीरियोटाइप बनाती है, जिसके अनुसार, सारे मुसलमान पिछड़े और धर्मांध हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद मीडिया ने ऐसे ही मुसलमानों को प्रमुखता से दिखाया है, जो तालिबानी फतह पर मस्त हैं। एक पाकिस्तानी कार्यक्रम में जब पूर्व नौकरशाह और अतिरेकी इस्लाम परस्त ओरिया मकबूल जान काबुल में शरिया नाफिज करने वाली हुकूमत के प्रजा वत्सल होने के कसीदे पढ़ रहे थे, तब नीचे आ रहे कमेंट्स में एक मुसलमान श्रोता की टिप्पणी बड़ी गौरतलब थी। उसने पूछा, यदि इतना ही बेहतरीन शासन आ गया है, तो हजारों-लाखों लोग सब कुछ छोड़-छाड़कर क्यों वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं या दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे पर ऐसे दृश्य क्यों नहीं दिख रहे, जिसमें मुस्लिम औरत-मर्द जिद कर रहे हों कि उन्हें किसी भी कीमत पर नए इस्लामी निजाम अफगानिस्तान में ले जाया जाए? दरअसल, ओरिया मकबूल जान का संकट भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर मुसलमानों के मन का द्वैत है, जो लगातार पश्चिम को कोसता भी रहता है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा या रोजगार के लिए बाहर भेजने के समय उसे अमेरिका या यूरोप की ही याद आती है।

इस पूरी बहस में मुंबई के मुस्लिम संगठन 'इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी' द्वारा जारी यह बयान नक्कारखाने में तूती की तरह गायब हो गया है कि अब धर्माधारित राज्य का समय खत्म हो गया है और अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात बनाने की कोशिश ही मनुष्य विरोधी है। अगर इस तरह की समझदार आवाज को जगह मिली, तो यह समझ भी बलवती होगी कि भारत में भी हिंदू राज के लिए कोई जगह नहीं है। हमें सावधान रहना होगा कि मुस्लिम कट्टरता पर हमले के बहाने कहीं हम हिंदू सांप्रदायिकता को तो बढ़ावा नहीं दे रहे? अगर ऐसा हुआ, तो काबुल की चिंता करते-करते हम खुद को नष्ट कर देंगे। इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के बयान का यह अंश भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुस्लिम उलेमा का यह शर्मनाक अवसरवाद है कि भारत में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वहां वे धर्मनिरपेक्ष निजाम चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में शरिया नाफिज करने का समर्थन कर रहे हैं।

प्रवीण कुमार सिंह

अफगानिस्तान में बदले हालात के हिसाब से सही दांव चलना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर

ऐसे में अलगाववादी तो इस प्रक्रिया में गतिरोध पैदा करने की फिराक में ही होंगे। हम उन्हें कोई मौका देना गवारा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में बदले हालात के हिसाब से अपने लिए सही दांव चलना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के इस भंवर में अपनी नैया पार लगाने में लगे हैं। इसके न केवल दीर्घकालिक सामरिक, बल्कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए भी गहरे निहितार्थ होंगे। साथ ही इससे नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका भी निर्धारित होगी। ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे घरेलू कारकों द्वारा सरकार को किसी भी प्रकार विचलित नहीं करना चाहिए।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तो सुनिश्चित थी, परंतु वह जिस अप्रत्याशित एवं औचक तरीके से हुई उसने पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया। आज समूचा अफगानिस्तान अराजकता की भेंट चढ़ा है। यह हमारे दौर की सबसे बड़ी मानवीय आपदाओं में से एक है। इसकी तुलना वियतनाम से अमेरिकी पलायन से की गई, परंतु इस संकट का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। काबुल की देहरी पर तालिबान की दस्तक के साथ ही अफगान सरकार घुटनों के बल आ गिरी। भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में मचे बवाल के कारण दुनिया के तमाम देश वहां से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हो उठे। काबुल एयरपोर्ट के नजदीक बम धमाकों से सुरक्षित वापसी की राह में भी अड़ंगे लगने लगे। इन परिस्थितियों में भारत के समक्ष चुनौतियां कई गुना बढ़ गईं। भारत के लिए अफगानिस्तान मात्र विदेश नीति का ही एक मसला नहीं, बल्कि हमारे लिए उसके कई घरेलू निहितार्थ भी हैं। जहां पश्चिमी जगत की अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक सक्रियता हालिया दौर की ही बात है वहीं अफगान के साथ हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। यह चिरकाल से हमारे विस्तारित पड़ोस का अहम हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की ठीक-ठाक आबादी थी। भारतीय कंपनियां वहां बुनियादी ढांचे से जुड़ी तमाम परियोजनाओं पर काम कर रही थीं। उनमें कार्यरत तमाम कामगार वहां फंस गए। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई। इसी के साथ-साथ अफगानिस्तान से अपने ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए हमने अफगान शरणार्थियों से भी मुंह नहीं मोड़ा। देश में महामारी के प्रकोप और अपने संसाधनों पर पहले से ही कायम दबाव के कारण अफगान लोगों को शरण देना आसान नहीं था।

वास्तव में अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे अपने मूल भावों के कारण हम मुसीबत में फंसे लोगों से मुंह मोड़ ही नहीं सकते। भारत जैसे विविधितापूर्ण और विशाल देश में अफगान संकट पर सरकार के रुख-रवैये को लेकर तमाम राय-मशविरे आए। एक बहस यह छिड़ी कि क्या भारत अफगान अल्पसंख्यकों जिनमें मुख्य रूप से हिंदू और सिख शामिल हैं, को ही वापस लाए या फिर बिना किसी धार्मिक आधार के शरण चाहने वाले सभी लोगों को आसरा दे। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए जैसे संवेदनशील मुद्दे का शिगूफा भी छेड़ा। अच्छी बात यह रही कि इसे लेकर विवाद छेड़ने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं, क्योंकि लोगों को जल्द समझ आ गया कि सरकार का रुख सुसंगत और पारदर्शी है। हालांकि, सुरक्षा के मोर्चे पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शरण देने की आड़ में कुछ आतंकी तत्वों के देश में पैठ बनाने को लेकर चिंता वाजिब है। फिलहाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बातें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेता कर रहे हैं। तालिबान की ताजपोशी का स्वागत कर और भारत सरकार को उससे संवाद की सलाह देकर उन्होंने एक तरह से अपनी मर्यादा रेखा लांघी। महबूबा मुफ्ती ने तो एक कदम आगे बढ़कर अफगानिस्तान और कश्मीर को एक ही तराजू में तौल दिया। यह न केवल आपत्तिजनक, अपितु भारत की आंतरिक राजनीति के लिए भी विध्वंसक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी जगत से लेकर पूरब में रूस और चीन जैसी शक्तियों के उलट अफगानिस्तान में भारतीय हितों की प्रकृति कुछ अलग है। इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी और तालिबान के साथ उसके संदिग्ध रिश्तों से सामरिक कोण बनता है। वहीं भारतीयों के दिलों में अफगान लोगों के लिए एक खास कोना है। इससे इनकार नहीं कि ऐतिहासिक रिश्तों के अलावा भारत की एक बड़ी आबादी विशेषकर उत्तर भारत में इस्लाम दोनों देशों के बीच एक साझा कड़ी रही है। एक ऐसे दौर में जब अफगानिस्तान के बदलते घटनाक्रम को लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इस्लामिक देश भी असमंजस में हैं तब हमारा रुख अभी तक सधा हुआ रहा है। ऐसे में नेताओं या सरकार के किसी बेमौका बयान के अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संदर्भ आगामी विधानसभा चुनाव विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। यह ईमानदार स्वीकारोक्ति करनी होगी कि चुनावों के दौरान सांप्रदायिक विभाजक रेखाएं बहुत गहरी हो जाती हैं। ऐसे में अगर नेता अफगानिस्तान संकट से मतदाताओं के ध्रुवीकरण और सियासी लाभ उठाने की जुगत भिड़ाएंगे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वैसे भी तालिबान की भारतीय मुस्लिमों या हिंदू के किसी वर्ग से कोई भी तुलना, जिसमें कुछ लोग लगे भी हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल होगी। हमारी पहचान अत्यंत विशिष्ट है, जिसे किसी आयातित विचारधारा द्वारा आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। हमें इस धारणा के साथ दृढ़ रहना होगा कि किसी धार्मिक आधार पर सबको एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि, इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम वास्तविक आतंकी खतरों को लेकर आंखें मूंदकर अपने रक्षा कवच को कमजोर कर लें। यह एक तथ्य है और अतीत का हमारा अनुभव भी यही पुष्ट करता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में विदेशी तत्वों ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। चुनाव और त्योहारी सीजन उनके हमलों के लिए माकूल मौका हो सकता है। कश्मीर में हालात धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सामान्य होने की सूरत में लौट रहे हैं। वहां चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अलगाववादी तो इस प्रक्रिया में गतिरोध पैदा करने की फिराक में ही होंगे। हम उन्हें कोई मौका देना गवारा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में बदले हालात के हिसाब से अपने लिए सही दांव चलना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के इस भंवर में अपनी नैया पार लगाने में लगे हैं। इसके न केवल दीर्घकालिक सामरिक, बल्कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए भी गहरे निहितार्थ होंगे। साथ ही इससे नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका भी निर्धारित होगी। ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे घरेलू कारकों द्वारा सरकार को किसी भी प्रकार विचलित नहीं करना चाहिए।

कोरोना टीकाकरण का क्रांतिकारी अभियान, भारत ने कायम की बड़ी मिसाल

विदेशी शासन से स्वतंत्र होने के सात दशक बाद हम एक अलग तरह की आजादी की तलाश कर रहे हैं। इस बार देश एक अदृश्य आक्रमणकारी वायरस से मुक्ति चाहता है, जो पिछले 20 महीनों से देश को तबाह करने पर तुला है। इस घातक वायरस के बारे में हम जो जानते हैं, उसके आधार पर दो रणनीतियां अपनाकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक प्रशासनिक स्तर पर जांच-निगरानी-उपचार और टीकाकरण रणनीति का पालन करना और दूसरा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कोविड-उपयुक्त व्यवहार के पालन को प्रोत्साहित करना। हालांकि, इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें इसके खिलाफ एक स्थायी प्रतिरक्षा की जरूरत थी। भारतीय विज्ञानियों और एजेंसियों ने रिकार्ड अवधि के भीतर कोविड-19 रोधी टीके विकसित करने के लिए भौतिक और तकनीकी सीमाओं से आगे जाकर काम किया और 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने भारत में निर्मित दो कोविड-19 टीके पेश करके दुनिया का सबसे बड़ा वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। कोविड-19 टीकों की वैश्विक शुरुआत के कुछ ही सप्ताह के भीतर भारत निर्मित टीकों की शुरुआत को भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास में एक उत्साहपूर्ण अभियान के रूप में देखा जा सकता है। हमें मिशन मोड में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के निर्माण का दुर्लभ अवसर मिला, जो वर्तमान के गंभीर संकट की तरह भविष्य के खतरों के खिलाफ मुकाबले के लिए हमें मजबूत बनाने के अलावा और भी कई अन्य कार्य करेगा।

देश मार्च 2020 से, जब कुछ शुरुआती कोविड मामलों का पता चला था, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों का निवेश कर रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन अनुसंधान और विकास के लिए उद्यमी अनुकूल परिवेश तथा नई निदान तकनीकों के विकास के साथ-साथ उपचार के नए तौर-तरीके भी स्थापित किए गए। मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत नए वैक्सीन प्लेटफार्म और उत्पाद विकास के अनुसंधान के लिए स्टार्ट-अप बायोटेक इकाइयों को तथा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए स्थापित वैक्सीन निर्माताओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विशेष और सक्रिय प्रयास किए गए। परिणामस्वरूप एक वर्ष से भी कम समय में टीकों का विकास, परीक्षण एवं अनुमोदन किया गया और एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुछ ही महीनों के भीतर देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित होने वाले मास्क, पीपीई किट, परीक्षण उपकरणों आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। कोविड के प्रति इन संवेदनशील उपायों ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया। वहीं, टीकाकरण की कवरेज में और तेजी लाने के उद्देश्य से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए टीका निःशुल्क करने के प्रधानमंत्री के निर्णय ने उच्चतम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ ही महीनों में भारत ने कोविड-19 के टीकों की 75 करोड़ से अधिक खुराकें दे दी हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हैं। इस समय, एक ही दिन में बड़ी तादाद में लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। मेरा यह दृढ़ मत है कि लोगों की पूरे दिल से सक्रिय भागीदारी ने ही इस टीकाकरण कार्यक्रम को इतना सफल बनाया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान, जिसका उद्देश्य इस साल के अंत तक देश की पूरी आबादी का टीकाकरण करना है, हमारे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलों को और अधिक बेहतरीन बनाने की दिशा में मूल्यवान सबक दे रहा है। आगे बढ़ता हुआ कोविड-19 टीकाकरण का यह कार्यक्रम हमारे नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, पानी और स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक कारगर प्रवेश द्वार बन सकता है। देश भर में हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से हुई वृद्धि से हमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हमारे स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के टीकों की 75 करोड़ खुराक देने की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम किया है, जो कि 'आजादी के अमृत महोत्सव' के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। दुनिया का सबसे बड़ा वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम भी 'आत्मनिर्भरता' के प्रति भारत के दृढ़संकल्प को और मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भरता को निश्चित रूप से समावेशी होना चाहिए। आवश्यक प्रौद्योगिकी के लिए पूरक सहयोग को अवश्य अपनाना चाहिए और इसके साथ ही सभी क्षेत्रों और देशों में आवश्यक अंतर-निर्भरता से लाभान्वित होना चाहिए। टीका अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन कार्य दरअसल राकेट विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम जैसा ही है। इसमें अनगिनत विज्ञानी, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन प्रक्रियाएं शामिल हैं। अतः एक ऐसा अनुकूल परिवेश बनाने की सख्त आवश्यकता है जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवश्यक कच्चे माल सहित टीकों के उद्यम और घरेलू उत्पादन को व्यापक प्रोत्साहन मिले।

मंत्रिमंडल परिवर्तन

गुजरात में विधानसभा चुनावों से करीब साल भर पहले मंत्रिमंडल का पूरी तरह कायापलट करके बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। चुनावों से कुछ समय पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बदलना कोई नई बात नहीं है। तमाम पार्टियां ऐसा करती रही हैं। जो बात गुजरात के इस प्रयोग को खास बनाती है, वह यह है कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल को भी बदल दिया गया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद उनकी जगह पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुनकर ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तगड़ा संदेश दे दिया था।

उसके बाद जब नए मंत्रिमंडल का शपथग्रहण हुआ, तब तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। उसमें पुराने मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। प्रदेश राजनीति में अपना एक मुकाम बना चुके इन नेताओं की इस पूरी पांत के लिए इस फैसले को पचाना मुश्किल होगा। ये लोग अभी इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्रियों का शपथ ग्रहण टालना पड़ा, उससे ऐसा लगा कि उनके मन में इस फैसले को लेकर असंतोष है। संभव है कि उनके करीबी समर्थक और कार्यकर्ता भी इसे पसंद न करें। लेकिन सत्ता विरोधी भावनाओं से निपटने के लिए बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों का टिकट काटना इधर के वर्षों में बीजेपी की जानी-पहचानी नीति रही है।

गौर करने की बात है कि गुजरात में मामला सिर्फ विजय रूपाणी सरकार का नहीं है। 2022 के चुनावों में वहां बीजेपी को सत्ता में 27 साल पूरे हो चुके होंगे। इनमें से दो दशक से ज्यादा की अवधि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व ही छाया रहा है। ऐसे में यह मानना स्वाभाविक है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद चाहे किसी के भी पास हो, प्रदेश विधानसभा चुनावों में असली परीक्षा मोदी-शाह नेतृत्व की ही होगी। 2017 विधानसभा चुनाव की मुश्किल भरी जीत के बाद पार्टी इस बार कोई जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं थी।

संभवतः इसीलिए पीएम मोदी की लोकप्रियता को हर लहर और जाति-धर्म के कारकों से ऊपर मानने वाली बीजेपी इस बार जातिगत समीकरण को साधने पर खास ध्यान दे रही है। स्वतंत्र भारत में पूरी पार्टी को अपने इशारों पर चलाने के मामले में इंदिरा गांधी की ही मिसाल दी जाती रही है, लेकिन वह भी मुख्यमंत्री बदलने तक ही सीमित रही थीं। किसी प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ दफा करने का साहस उन्होंने भी कभी नहीं किया था। आज अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसा कर पाया है और हटाए जाने वाले नेताओं की ओर से इसका खुलकर विरोध नहीं हो रहा है तो इसका यह भी मतलब है कि पार्टी पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो अब इंतजार कीजिए इस प्रयोग के नतीजों का।

समाज सेवा की आड़ में साजिश, मतांतरण के गंदे धंधे में विदेशी चंदे पर जरूरी है प्रहार

इसके बाद भी यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की निगाह में सभी बराबर हैं। यह निरा झूठ है। सच यह है कि हमारा संविधान समानता के सिद्धांत की घोर अनदेखी करता है। पता नहीं क्यों संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यह विसंगति दिखाई नहीं देती। यह विसंगति शिक्षा अधिकार कानून में भी नत्थी हो गई है। माना जाता है कि इसी कारण हिंदू समाज का अंग माने जाने वाले जैन समाज ने खुद को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की पहल की। एक तरह से भारतीय संविधान ही भारतीय समाज के विघटन-विखंडन को बढ़ावा दे रहा है।

हाल में केंद्रीय गृह मंत्रलय ने करीब छह गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के उस लाइसेंस को रद कर दिया, जिसके तहत वे विदेशी चंदा लेने के अधिकारी थे। इस तरह इस साल ऐसे गैर सरकारी संगठनों की संख्या नौ पहुंच गई है, जिनके विदेशी चंदे पाने वाले लाइसेंस को रद किया गया। इन संगठनों पर विदेश से मिले चंदे का दुरुपयोग करने, आय-व्यय का हिसाब न देने और मतांतरण में लिप्त होने जैसे गंभीर आरोप हैं। बीते कुछ सालों में इन्हीं कारणों से तमाम गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदे हासिल करने वाले लाइसेंस रद किए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे हजारों संगठन सक्रिय हैं। ऐसे संगठन प्रकट रूप में तो समाज सेवा का काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर मतांतरण का गंदा धंधा चलाते हैं। वे विदेश से मिले पैसे का मनमाना इस्तेमाल करते हैं। जहां कुछ एनजीओ अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, वहीं अन्य लोगों को बरगलाकर या फिर उनकी गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका मत-मजहब बदलने का काम करते हैं।

वैसे तो मतांतरण का धंधा पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन अफ्रीका और एशिया के गरीब देश किस्म-किस्म के गैर सरकारी संगठनों के निशाने पर खास तौर से हैं। इनमें से बड़ी संख्या उनकी है, जो दूसरे मत-मजहब वालों को अपने मजहब में लाने को प्रतिबद्ध हैं। इनका मानना है कि लोगों का भला तभी होगा, जब वे मजहब विशेष के अनुयायी बनेंगे। जाहिर है कि ऐसे ज्यादातर संगठन ईसाइयत या इस्लाम से जुड़े हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों मजहब के धर्म प्रचारक इस

मानसिकता से लैस हैं कि केवल उनका मार्ग ही असली या फिर एकमात्र ऐसा मार्ग है, जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है या फिर जन्नत को हासिल किया जा सकता है। ये संगठन-समूह इस सनक से ग्रस्त हैं कि सारी दुनिया को अपने मजहब का अनुयायी बनाना है। इन संगठन-समूहों को कई देशों की सरकारें भी संरक्षण देने के साथ आर्थिक सहायता भी देती हैं। यदि कोई देश ऐसे संगठन-समूहों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वहां धार्मिक स्वतंत्रता के खतरे में होने का झूठा प्रचार किया जाता है। इस काम में तथाकथित मानवाधिकार संगठन भी भागीदार बनते हैं।भारत में मतांतरण में लिप्त संगठनों का काम इसलिए आसान बना हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी मतावलंबियों को अपने मत-मजहब का प्रचार करने का अधिकार देता है। इस अधिकार में कोई समस्या नहीं। समस्या इसमें है कि इसका जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दुरुपयोग का उदाहरण है पूवरेत्तर भारत के साथ-साथ देश के आदिवासी बहुल इलाके। इन इलाकों में बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों का मतांतरण वैसे ही गैर सरकारी संगठनों की ओर से किया जा चुका है, जैसे कुछ संगठनों पर रह-रहकर पाबंदी लगाने का सिलसिला कायम है। मतांतरण में लिप्त संगठन कितने दुस्साहसी हैं, इसका एक प्रमाण है कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उस इस्लामिक दावा सेंटर का भंडाफोड़, जो मूक-बधिर छात्रों को मतांतरित करने में लगा हुआ था। ऐसे ही तमाम संगठन ईसाई मिशनरियों की शक्ल में सक्रिय हैं। ये इतने ढीठ हैं कि लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू देवी-देवताओं की आड़ लेने में भी संकोच नहीं करते। ऐसे संगठन अब सारे देश में सक्रिय हैं। उनकी अवांछित सक्रियता से सरकारें अच्छी तरह अवगत हैं, लेकिन वे कुछ करने से बचने में ही अपनी भलाई समझती हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि मतांतरण अभियान कुल मिलाकर राष्ट्रांतरण का काम कर रहा है। जब कभी मतांतरण में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात उठती है तो खुद को सेक्युलर-लिबरल कहने वाले सक्रिय हो उठते हैं। ऐसे लोग तब भी सक्रिय हो जाते हैं, जब कोई संगठन घर वापसी की बात करता है।

जिन सेक्युलर-लिबरल तत्वों को छल-छद्म से चल रहे मतांतरण अभियानों से कोई समस्या नहीं होती, वे घर वापसी जैसे कार्यक्रमों पर आपत्ति जताते हैं। यही नहीं, वे दलितों और आदिवासियों को हिंदू न मानने की वकालत करने वालों का साथ देते हैं। यह ऐसे तत्वों की सक्रियता का प्रमाण है कि अब मीडिया के एक हिस्से में ऐसा विमर्श दिखाई देने लगा है कि किस क्षेत्र में कितने हिंदू, मुसलमान और दलित एवं आदिवासी हैं। यह और कुछ नहीं दलितों और आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग बताने का कुचक्र है।

मतांतरण में लिप्त तत्व इसलिए बेलगाम हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक एवं शिक्षा संस्थानों को अपने हिसाब से संचालित करने का अधिकार है। इस अधिकार का भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। यह अधिकार बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं है और इसी कारण यह मांग उठती रहती है कि मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। ज्ञात हो कि देश के ज्यादातर बड़े मंदिरों का प्रबंधन सरकारों की ओर से किया जाता है। उनके चंदे और चढ़ावे का पैसा सरकारी कोष में जाता है। इसका कहीं कोई औचित्य नहीं कि अपने धार्मिक स्थलों और शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन का जैसा अधिकार अल्पसंख्यकों को हासिल हो, वैसा बहुसंख्यकों को न हो, लेकिन यह अंधेरगर्दी जारी है।

इसके बाद भी यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की निगाह में सभी बराबर हैं। यह निरा झूठ है। सच यह है कि हमारा संविधान समानता के सिद्धांत की घोर अनदेखी करता है। पता नहीं क्यों संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यह विसंगति दिखाई नहीं देती। यह विसंगति शिक्षा अधिकार कानून में भी नत्थी हो गई है। माना जाता है कि इसी कारण हिंदू समाज का अंग माने जाने वाले जैन समाज ने खुद को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने की पहल की। एक तरह से भारतीय संविधान ही भारतीय समाज के विघटन-विखंडन को बढ़ावा दे रहा है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

बिहार का पहला अत्याधुनिक पुल भागलपुर में बनेगा, स्टील फाइबर लगने से सौ साल से ज्यादा होगी उम्र, अक्टूबर से निर्माण

भागलपुर । विक्रमशिला के समानांतर फोर लेन पुल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से होगा। पुल की उम्र सौ साल से यादा हो इसलिए ब्रिज को स्टील फाइबर (रिइंफोर्सड कंक्रीट टेक्नोलॉजी) व एक्स्ट्रा डोज का इस्तेमाल कर बनाया जाएगा। ताकि पुल की उम्र सौ साल से यादा हो। इस तकनीक से पुल की लागत भी कम होगी। उसके रखरखाव में समस्या कम होगी। इस तकनीक से बनने वाला पुल सूबे का पहला होगा। पुल की डिजाइन का काम रोडिक कंसल्टेंट को मिला। इस डिजाइन को बनाने के लिए अमेरिका की कंपनियों से सहयोग लेने की बात हो रही है। हाल में ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विक्रमशिला पुल के समानांतर प्रस्तावित फोरलेन पुल के निर्माण और अत्याधुनिक तकनीक की डिजाइन को लेकर बैठक की थी। बैठक में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रोडिक कंसल्टेंट के इंजीनियर भी शामिल थे। बैठक के बाद अत्याधुनिक तकनीक की डिजाइन को बनाने में तेजी आई है। गंगा नदी पर विक्रमशीला सेतु के समानांतर 4.367 किमी लंबे नए फोर लेन पुल को अगले चार साल में पूरा करने का लक्ष्य है। जो डिजाइन बनाया जा रहा है, उसमें 4.367 किमी लंबे सेतु के साथ नवगछिया की ओर 875 मीटर और भागलपुर की ओर 987 मीटर पहुंच पथ भी शामिल है। सेतु के पूरा होने के बाद, भागलपुर शहर में यातायात सुगम हो जाएगा और वाहन झारखंड से प्रवेश कर सकेंगे। इस नए फोरलेन सेतु के बनने से नवगछिया से भागलपुर होते हुए झारखंड की सीमा तक पहुंच आसान हो जाएगा। यह सेतु बिहार और झारखंड के बीच यातायात को और सुविधाजनक बनाएगा। इस सेतु के बन जाने से कोसी-सीमांचल और पूर्व बिहार के जिलों को लाभ मिलेगा। यहीं नहीं पश्चिम के जिलों और अन्य सेतुओं का बोझ भी काफी कम होगा। राय के सीमांचल का झारखंड के साथ सड़क संपर्क तो सुगम होगा ही, पश्चिम बंगाल के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा पूर्वोत्तर के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा। रोडिक कंसल्टेंट के निदेशक मनोज कुमार ने कहा, इस परियोजना के लिए भारत में नई तकनीक को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह सेतु कार्गो और अन्य जरूरी सामानों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कई गुणा प्रभाव डालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पितृपक्ष में श्राद्ध करना संभव ना हो तो गाय को खिलाएं चारा-दाना, जानिए कैसे चुका सकते पितृ ऋण

जमशेदपुर। हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण बताए गए हैं। इनमें से पितृ ऋण चुकाने के लिए पितरों की मुक्ति के लिए प्रयास करना आवश्यक है। पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना महत्वपूर्ण है। हिंदू जनजागृति समिति के जमशेदपुर से जुड़े सुदामा शर्मा ने बताया कि इस बारे में समिति के धर्मप्रसारक संत नीलेश सिंगबाळ ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें संभव है, वे पितृपक्ष में पुरोहितों को बुलाकर श्राद्ध विधि करें। परंतु कोरोना के कारण पुरोहित अथवा श्राद्ध सामग्री के अभाव में जिन लोगों के लिए श्राद्ध करना संभव न हो, वे आपद्धर्म के रूप में संकल्पपूर्वक आमश्राद्ध, हिरण्यश्राद्ध, गोग्रास (गाय को चारा-दाना) अर्पण करें।

नित्य करें एक-दो घंटे करें नामजप- इसके साथ ही पूर्वजों को आगे की गति प्राप्त होने हेतु और अतृप्त पूर्वजों से कष्ट न हो, इसलिए नियमित रूप से साधना करें। श्राद्ध विधि के साथ ही पितृ पक्ष में अधिक से अधिक समय या प्रतिदिन कम से कम एक से दो घंटे 'श्री गुरुदेव दत्त' नामजप सभी को करना चाहिए। नीलेश सिंगबाळ ने कहा कि हिंदुओं में धर्मशिक्षा का अभाव, पश्चिमी अंधानुकरण और हिंदू धर्म को तुच्छ मानने की प्रथा के कारण अनेक बार श्राद्ध विधि की अनदेखी की जाती है। इसके बावजूद आज भी अनेक पश्चिमी देशों के हजारों लोग भारत के तीर्थक्षेत्रों में आकर पूर्वजों को आगे की गति प्राप्त होने के लिए श्रद्धा से श्राद्ध विधि करते हैं। प्रथम श्राद्ध विधि 'मनु' ने की थी। 'राजा भगीरथ' ने पूर्वजों की मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी। त्रेतायुग में प्रभु रामचंद्र के काल से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के काल तक श्राद्धविधि का उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए तथाकथित आधुनिकतावादियों द्वारा श्राद्ध के विषय में किए गए किसी भी दुष्प्रचार में न फंसें। कोरोना महामारी के काल में अपनी क्षमतानुसार पितृऋण चुकाने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध विधि करें।

नीलेश सिंगबाळ ने बताया कि श्राद्ध न करने पर हमारे पूर्वज अतृप्त रहने से दोष निर्माण होता है। श्राद्ध विधि के कारण पूर्वजों को मर्त्य लोक से आगे जाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। मृत्यु के उपरांत भी सद्गति के लिए श्राद्धविधि बतानेवाला हिंदू धर्म एकमात्र है। वर्तमान में समाज में धर्म शिक्षा के अभाव में श्राद्ध करने के स्थान पर सामाजिक संस्था अथवा अनाथालयों को दान दें, ऐसी भ्रामक संकल्पना का प्रचार किया जाता है। ऐसा करना अनुचित है। धार्मिक कृति धर्मशास्त्रानुसार करनी ही आवश्यक है। तदनुसार कृति करने पर ही पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं।

विधायक नवीन जायसवाल ने कहा, रूपा तिर्की के परिजनों को सीबीआइ जांच के बदले प्रलोभन देना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा

रांची । झारखंड प्रदेश भाजपा के मंत्री एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि खुद को आदिवासियों का मसीहा/हितैषी बताने वाले नेता ही जब निश्छल (भोले-भाले) आदिवासी भाई-बहन किस पर विश्वास करें.. न्याय और अन्याय की लड़ाई में कौन उनके साथ खड़ा होगा..? विगत दिनों झारखंड की बेटी रूपा तिर्की की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हो जाती है,उसके परिजनों के साथ-साथ पूरा विपक्ष चीख-चीख कर सीबीआइ जांच की मांग सरकार से करता है। मगर झारखंड सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। उन्होंने कहा कि खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली राज्य सरकार और उसका पूरा सरकारी महकमा दोषियों को बचाने में जुट जाता है, सिर्फ इसलिए कि आरोप एक ऐसे शख्स पर है जो सूबे के मुखिया का सबसे करीबी है,और उनका प्रतिनिधि भी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और आदिवासियों के स्वघोषित मसीहा सत्तारूढ़ दल के एक विधायक आदिवासी बेटी की मौत का सौदा करने पहुंच जाते हैं। रूपा के परिजनों को सीबीआइ जांच की मांग नहीं करने के लिए प्रलोभन देते हैं। डीएसपी रैंक का एक अधिकारी रूपा के पिता को धमकी देता है,उस पर झूठे मुकदमे करवाता है, सिर्फ इसलिए की न्याय की जो मांग उसके परिजन कर रहे हैं ,उसे दबाया जा सके। उन्होंने कहा, क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग भी नहीं कर सकता ? एक आदिवासी परिवार की बेटी का छोटे से गांव से सीमित संसाधनों में पढ़-लिख कर दरोगा बनना पूरे राज्य के लिए गौरव की बात थी। रूपा अपने कार्यों एवं ईमानदारी की वजह से पूरे राज्य का नाम रौशन कर रही थी। अचानक उसकी मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हो जाती है। मस्तिष्कघात उसकी तस्वीरें और अन्य कई परिपेक्ष्यों को सुनने व देखने के उपरांत साफ-साफ प्रतीत होता है कि रूपा की मृत्यु पूरी तरह संदिग्ध है।

संभव है कि रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हो गई हो,पर सत्ता में बैठे लोग अपनी पोल खुलने के डर से उसकी मौत का सौदा करने में लगे हुए थे। अब जबकि उच्च न्यायालय ने रूपा तिर्की की मौत को असामान्य मानते हुए सीबीआइ जांच कराने की बात कही है तो सीबीआइ को यह भी जांच करनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में और किस मकसद से कांग्रेस पार्टी के विधायक बंधु तिर्की रूपा के परिजनों को सीबीआइ जांच की मांग नहीं करने और राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से ही जांच करवाने के फैसले पर सहमति जताने के लिए बाध्य कर रहे थे। कहीं ये अपरोक्ष रूप से दोषियों को बचाने की कवायद तो नहीं थी..? आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि विधायक को घंटों बैठ कर सीबीआइ की कमियां और उसकी बुराई बताने तथा राज्य सरकार द्वारा गठित टीम की तारीफ के पुल बांधने पड़े। सीबीआइ जांच के दौरान मिले ऑडियो क्लिप से ये साफ जाहिर होता है कि सरकार के दूत के रूप में बंधु तिर्की पीड़ित परिवार को सीबीआइ जांच की मांग के बदले कई प्रलोभन देने में जुटे हुए हैं,ऐसे में ऑडियो में की गई वार्ता को भी संदेहास्पद मानते हुए सीबीआइ को इसकी दूसरे पहलुओं को भी खंगालना चाहिए। एक आदिवासी बेटी के न्याय की लड़ाई को कौन और क्यों दबाना चाहता है,ये सत्य सबके सामने आना चाहिए। झारखंड की बेटी को हर हाल में इंसाफ मिलना ही चाहिए।

अवैध मतांतरण केस में यूपी एटीएस को एक और कामयाबी, मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरतार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में एक हजार से अधिक लोगों का अवैध ढंग से मतांतरण (धर्मांतरण) कराने के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की कार्रवाई जारी है। अवैध मतांतरण मामले में यूपी एटीएस ने एक और आरोपित मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वह जमीयत-ए-वलीउल्लाह ट्रस्ट का अध्यक्ष है। मतांतरण मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित उमर गौतम के संपर्क में रहे कलीम की भी सक्रिय भूमिका सामने आई है। कलीम के खिलाफ विदेश से तीन करोड़ रुपये की फंडिंग के साक्ष्य मिले हैं। उमर गौतम व अन्य आरोपितों के साथ उसके रिश्तों की छानबीन चल रही है।

मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के फूलत निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी और कई अन्य लोगों को मंगलवार रात यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया था। रात भर इनसे पूछताछ की गई। इसके बाद बुधवार को इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा राजफाश किया। यूपी एटीएस के अनुसार मौलाना सिद्दीकी दिल्ली में रहता है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध मतांतरण के कार्य को अंजाम देता है जिसके लिए विदेश से फंडिंग की जाती है। वह गैर मुस्लिमों को गुमराह और डराकर कर उनका मतांतरण करता है।

मौलाना कलीम सिद्दीकी मंगलवार शाम को अन्य मौलानाओं के साथ मेरठ के लिसाड़ीगेट में हूमायुंनगर की मस्जिद माशाउल्लाह के इमाम शारिक के आवास पर एक कार्यक्रम में आया था। रात में इशा की नमाज के बाद वह अपने साथियों के साथ गाड़ी से वापस फुलत के लिए रवाना हो गया। इस दौरान परिवारीजन ने फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। परिजनवारी ने जानकारी मेरठ में इमाम शारिक को दी। सभी ने मौलाना की तलाश शुरू की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद लोगों की भीड़ लिसाड़ीगेट थाने पर जुट गई। देर रात तक हंगामा चलता रहा। कुछ समय बाद जानकारी मिली कि मौलाना को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है।

अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चर्चा यह भी है कि पूर्व बालीवुड फिल्म अभिनेत्री सना खान का निकाह मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही कराया था। सना खान ने अपना फिल्मी करियर छोड़कर एक मौलाना से निकाह करने के बाद इस्लामिक परंपरा से जीवन व्यतीत करने का फैसला किया था, जो काफी चर्चा का विषय बना था। अब मतांतरण के मामले में मौलाना सिद्दीकी से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले राजफाश हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में हजार से अधिक लोगों के मतांतरण मामले के आरोपितों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को बहरीन से 1.5 रुपये सहित विदेशी फंडिंग में तीन करोड़ रुपये मिले हैं। वह जमीयत-ए-वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाता है, जिसके जरिए कई मदरसों को फंडिंग की जाती है। इस मामले की पड़ताल के लिए एटीएस की छह टीमों का गठन किया गया है।

बता दें कि एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने 20 जून को प्रेसवार्ता कर उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों तक फैले मतांतरण के रैकेट का राजफाश किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपितों को आइएसआइ से भी फंडिंग की जा रही थी। मूक-बधिक बच्चों से लेकर महिलाओं व कमजोर वर्ग के लोगों का साजिश के तहत बड़े पैमाने पर मतांतरण कराया जा रहा था। उस समय गिरफ्तार किए गए दिल्ली के जामियानगर के मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी ने विदेश से फंडिंग से जुड़े कई अहम राज उगले थे। कई खातों की जानकारी भी सामने आई थी। खासकर उमर गौतम के आइएसआइ कनेक्शन को लेकर भी कई तथ्य मिले थे।

गिरफ्तार किए गए उमर दौतम और जहांगीर ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन लोगों ने धन का लालच देकर एक हजार से अधिक लोगों का मतांतरण करवाया। इस काम के लिए आइएसआइ से फंडिंग होती थी। ये लोग मूक और बधिर बच्चों और महिलाओं को टार्गेट करते थे। मतांतरण के बाद महिलाओं की शादी भी कराई गई। इस काम के लिए एक पूरा गिरोह सक्रिय है। यह रैकेट और भी कई राज्यों में सक्रिय होने की बात सामने आई थी। इन दोनों लोगों ने मथुरा और वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में अभियान चलाकर मतांतरण करवाया था।

जीतनराम ने उठाया राम पर सवाल तो बीजेपी हुई गर्म, बिहार में राजद ने पूछा तल्ख सवाल, जदयू ने साधी चुप्पी

पटना। बिहार में भगवान श्रीराम के नाम पर बवाल हो गया है। भाजपा के कुछ नेताओं ने उनकी जीवनी स्कूलों में पढ़ाने की मांग उठाई तो इसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब अलग ही रूप लेने लगा है। राय के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार में शामिल दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इसके बाद सरकार की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पूरी तरह गर्म है तो सरकार का दूसरा प्रमुख दल जदयू पूरी तरह चुप्पी साध लिया है। इसका नतीजा है कि राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां एनडीए की सरकार और इसमें शामिल दलों पर सवाल उठा रही हैं। राजद ने भाजपा से पूछा है कि उनकी पार्टी जीतनराम के साथ है या भगवान श्रीराम के साथ

सहयोगी दल पर भाजपा का रवैया गर्म

जीतनराम मांझी के बयान से बिहार के भाजपा नेताओं में गुस्सा है और अपने ही सहयोगी दल की ओर से राम पर सवाल खड़ा किए जाने के बाद उनके सामने एक धर्मसंकट भी खड़ा हो रहा है। भाजपा के विधायक और राय के पथ निर्माण मंत्री नीतीन नवीन ने कहा कि खुद को सेकुलर दिखाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। मांझी का बयान सही नहीं है और सचाई के विपरीत है। वहीं भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि राम को नकारने वाले बहुत से लोगों ने अब राम-राम करना शुरू कर दिया है। जो बचे हैं वे भी बहुत जल्द सुधर जाएंगे।

कांग्रेस और राजद ने गठबंधन पर उठाए सवाल- कांग्रेस और राजद के नेताओं ने भाजपा और हम के बीच गठबंधन पर भी सवाल खड़ा किया है। दोनों दलों के नेता भाजपा के साथ ही हम से भी इस मसले पर सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि मांझी अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो वे राम के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करने वालों के साथ क्यों खड़े हैं। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि वे जीतनराम के साथ हैं या राम के साथ।

जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र में छूट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

रांची। जेपीएससी परीक्षा-2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमआर शाह एवं जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद सिविल सेवा परीक्षा नहीं हुई है। इसलिए वर्ष 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 रखी गई है। जेपीएससी की ओर से यह भी कहा गया कि इसके लिए 19 सितंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा हो गई है। ऐसे में उम्र में छूट देना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के उम्र सीमा निर्धारण को सही मानते हुए प्रार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ रीना कुमारी सहित अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि यह सिर्फ उम्र की सीमा निर्धारण का मामला नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से बनाई नई नियमावली को पीछे की तिथि

चोरी करते समय दानपात्र में फंस गया हाथ, रातभर तड़पता रहा किशोर चोर

कन्नौज । कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है और सजा भी देता है। कुछ ऐसा ही कन्नौज के एक गांव में मजार में किशोर के साथ हुआ, यहां चोरी करने आए किशोर का हाथ दानपात्र से धन निकालते समय फंस गया। उसका हाथ ऐसा फंसा कि फिर निकल न सका और पूरी रात वह दर्द से तड़पता रहा और साथी भी उसे छोड़कर फरार हो गए। सुबह उसके रोने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। सूचना पर आई पुलिस ने उसका हाथ दानपात्र से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया है।

कन्नौज सदर कोतवाली के गांव मड़हारपुर में बाबा हज़रत लाल शहीद की मजार है। सोमवार रात किशोर अपने साथी चौधरियापुर निवासी के साथ मजार पहुंचा। यहां रखे लोहे के दानपात्र से पैसे चोरी करने का प्रयास किया। मगर ताला लगा होने के कारण कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा दोनों ने किसी तरह सरिया या लोहे की दूसरी चीजों की मदद से दानपात्र का ऊपरी हिस्सा उचका दिया। इसके बाद एक किशोर ने उसमें हाथ डाल दिया। पैसे निकालने के दौरान उसका हाथ फंस गया। काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रातभर कोशिश करता रहा, मगर हाथ नहीं निकला। सुबह हुई तो उसका साथी वहां से भाग गया, जिसका हाथ दानपात्र में फंसा था वह वहीं बैठा-बैठा रोने लगा।

उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग मजार पहुंचे। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मजार की देखरेख करने वालों से चाभी मंगाकर दानपात्र का ताला खुलवाया और युवक का हाथ बाहर निकाला। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली प्रभारी विकास राय ने बताया कि किशोर मैनपुरी का रहने वाला है। वह मानीमऊ स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करता है। वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बताया जा रहा है उसे कैंसर है। किशोर को उनके स्वजन के हवाले कर दिया गया है। मामले में तहरीर नहीं मिली है, लिहाजा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है।

विदुरकुटी में बनेगा प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

बिजनौर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाभारत सर्किट से जुड़े विदुर कुटी स्थल में प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहां देश की प्राचीन पद्धति पर शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से यहां पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और नगरी को विकास के पंख लगने की उम्मीद जगी है। साथ ही योगी ने बिजनौर में बनने वाले मेडिकल कालेज का नाम भी विदुर के नाम पर रखने की घोषणा की।

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मधुसूदन देवीदास गांव में राजकीय मेडिकल कालेज का शिलान्यास करने पहुंचे। यहां उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही महात्मा विदुर को नमन किया। उन्होंने भारत के इतिहास का विदुर को साक्षी बताया और महाराजा दुष्यंत और उनके पुत्र की गाथा सुनाई। महाकवि कालीदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में बिजनौर महाराजा दुष्यंत की प्रणय स्थली है। उनकी पहचान संतान भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। इससे सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। उन्होंने इस नगरी के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने विदुर कुटी में प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र की स्थापित किए जाने की घोषणा की। इस अध्ययन केंद्र में देश की प्राचीन पद्धति पर शिक्षा देने के साथ ही शोध भी किए जाएंगे और यहां पौराणिक ग्रंथ भी उपलब्ध होंगे। इस अध्ययन केंद्र के स्थापित होने के बाद विदुरकुटी के आसपास के लोगों को विकास की उम्मीद जगी है। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मधुसूदनपुर देवीदास में 281.52 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय मेडिकल कालेज का शिलान्यास किया। मेडिकल कालेज में 500 बेड का अस्पताल होगा और शिक्षण सत्र वर्ष 2022-23 में एमबीबीएस में 100 सीटों पर प्रवेश देने की व्यवस्था की गई। केंद्रीय सहायतित योजना फेज-तीन के अंतर्गत ग्राम मधुसुदनपुर देवीदास की करीब छह सौ बीघा भूमि में निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कालेज में प्रशासनिक ब्लाक, एकेडमिक ब्लाक, लाइब्रेरी, मल्टी परपज हाल, जिम, 350 छात्रों की क्षमता योग्य छात्रवास, आवासीय भवन और धर्मशाला ब्लाक होगा। वहीं, मरीजों के लिए पांच सौ बेड की क्षमता का अस्पताल भी होगा। मेडिकल कालेज में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय कालोनी भी बनाई जाएगी। 18 माह में मेडिकल कालेज का निर्माण होने के बाद जनपद के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। जिले में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं न होने से दुर्घटना में गंभीर घायलों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ, दिल्ली, जौली ग्रांट और ऋषिकेश एम्स में ले जाना पड़ता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं उपकरणों की कमी से जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल रेफरल सेंटर बन कर रहे गए थे। मधुसूदनपुर देवीदास मेडिकल कालेज के निर्माण के बाद बिजनौर के लोगों को समय पर इलाज मिलेगा। वहीं आसपास के क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास होने के साथ-साथ कारोबार में वृद्धि और रोजगार बढ़ेगा।

योगी बोले, इस बार मत चूक जाना- जनपद में पांच विधायक भाजपा से हैं, जबकि तीन विधायक सपा के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगीना, नजीबाबाद और नूरपुर में भाजपा विधायक होते, तो इन क्षेत्रों में और भी ज्यादा विकास होता। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक जब भी लखनऊ आते थे, तब-तब अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाने की बात करते रहे। यही वजह है कि भाजपा विधायकों के क्षेत्र में अधिक काम हुए।

इन घोषणाओं का रहा इंतजार

पूरे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा के बाएं किनारे बसे 51 गांवों को बाढ़ के दंश से बचाव के लिए स्थायी बंदोबस्त किए जाने, काष्ठ कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई राहत देने की घोषणा नहीं की। लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ न कुछ देकर जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हेलीकाप्टर से मधुसूदनपुर देवीदास पहुंचे। सीएम ने जैसे ही हेलीकाप्टर से विदुर की धरती पर पैर रखा, तो पंडाल में शंख बजने शुरू हो गए। पंडितों द्वारा माइक पर मंत्रोच्चार होने लगा। कुछ पल को सभा व शिलान्यास स्थल के पास मंदिर जैसा माहौल हो गया था। इस दौरान मंच से जय श्रीराम के नारे लगते रहे और पंडाल में समर्थक शंख बजाते रहे। मंच पर पहुंचने पर स्थानीय नेताओं ने भगवान की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बोले- उद्धाटन से पहले ही पड़ी दरार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में हल्की दरार पड़ गई थी। इसकी जानकारी होते ही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल दरार की मरम्मत करवाई। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्माण और भ्रष्टाचार के बीच ऐसा करार हुआ कि उद्घाटन से पहले ही दरार पड़ गई।

यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में निर्माण और भ्रष्टाचार के बीच ऐसा करार हुआ कि उद्घाटन से पहले ही दरार पड़ गई। काम के नाम पर इन्होंने केवल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का नाम ही बदला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाते-बनाते मान्यवर स्वयं पूर्व मतलब भूतपूर्व हो जाएंगे।

बता दें कि 23 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 340 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लाइफलाइन कहा जा रहा है। यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने के साथ ही अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिलों से होता हुआ गुजरेगा। इस एक्सप्रेस-वे से लिंक रोड के जरिए गोरखपुर और वाराणसी जैसे अहम शहर जुड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत लखनऊ-सुलतानपुर रोड (एनएच-731) पर स्थित गांव चांद सराय से होगी और गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव पर यह खत्म होगा। हैदरिया गांव यूपी और बिहार की सीमा से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

राजद सुप्रीमो लालू यादव प्रसाद बोले- हरे रंग की टोपी और गमछा ही आपका लाइसेंस

पटना । बिहार के राजद कार्यकर्ताओं को अब ड्रेस कोड का पालन करना होगा। यह राजद सुप्रीमो ने ही तय कर दिया है। दरअसल राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार में राजद कार्यकर्ताओं को नई पहचान दी है। अब राजद के कार्यकर्ता और नेता हरी गमछी और टोपी पहने नजर आएंगे।

राजद के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन बुधवार को राजद कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को आनलाइन संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के समर्थकों की पहचान टोपी है, उसी तरह राजद के नेता और कार्यकर्ता हरी गमछी और टोपी पहनें। यही आपका लाइसेंस है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कार्यकर्ताओं को अपने घरों के आगे राजद का झंडा लगाने की भी सलाह दी है, ताकि पहचान हो सके कि यह राजद समर्थक का घर है।

पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर राजद के दो दिवसीय प्रशिक्षण सह सम्मान शिविर के समापन सत्र में पार्टी सुप्रीमो ने अपनी बातें रखीं। कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठावान बनें। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गहरे लाल रंग की टोपी पहनते हैं।

चाहे वे पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव हों या फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव, सभी सार्वजनिक जगहों पर भी लाल रंग की टोपी में नजर आते हैं। इसी तरह अब राजद के कार्यकर्ता भी हरी गमछी और टोपी में नजर आएंगे। हालांकि राजद का प्रतीक चिह्न या झंडा पहले से ही हरे रंग का है। लेकिन अब एक राजद का ड्रेस कोड भी सुप्रीमो ने तय कर दिया है।

मालूम हो कि दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को नेता प्रतिपक्ष समेत शिवानंद तिवारी, अब्दुलबारी सिद्दीकी, श्याम रजक, बृषण पटेल, मनोज झा, उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने भी संबोधित किया। इस दौरान सभी जाति-धर्म के लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील कार्यकर्ताओं से की गई।

समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में बड़ा फैसला, एलजेपी नेता समेत 13 दोषियों को उम्रकैद

समस्तीपुर । पत्रकार विकास रंजन की हत्या मामले मे एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय ने 13 अभियुक्तों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। इससे पूर्व 15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। 13 वर्ष पूर्व की चर्चित घटना से संबंधित सत्र वाद संख्या 205/10 की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने प्राथमिकी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 एवं 120 बी में दोषी करार दिया है। जिसमें हसनपुर थाना के बसतपुर निवासी स्व. रामखेलावन चौधरी के पुत्र उमाकांत चौधरी, स्वर्गीय शत्रुध्न राय के पुत्र विधानचंद्र राय, विधान चंद्र राय के पुत्र राजीव रंजन एवं प्रियरंजन, शिवचंद्र चौधरी के पुत्र मनोज कुमार चौधरी एवं मनेन्द्र कुमार चौधरी तथा बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत नारायणपीपुर निवासी शोभा कांत राय का पुत्र रामउदय राय एवं रामउदय राय का पुत्र राजीव राय तथा संजीव राय शामिल है। वहीं, पुलिस अनुसंधान में शामिल किए गए मामले के अप्राथमिकी अभियुक्त बिथान थाना के लरझा निवासी सिफैती यादव का पुत्र मोहन यादव एवं उक्त गांव के ही राम स्वार्थ यादव का पुत्र कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव के अलावा साहेबपुर कमाल थाना के हरदिया, वर्तमान में रोसड़ा के दामोदरपुर निवासी हीरा सिंह के पुत्र बबलू सिंह, बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर के कुंभी निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र संतोष आनंद सिंह तथा महुली के शिव कुमार यादव का पुत्र स्वयंवर यादव को न्यायालय ने भादवि की धारा 302/34 एवं 120 बी तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। 13 अभियुक्तों को जेल भेज दिया जबकि न्यायालय से गायब रहे मोहन यादव के विरुद्ध कुर्क वारंट जारी किया गया। सुनवाई के दौरान सरकार एवं वादी पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार एवं बेगूसराय के अधिवक्ता एजाजुल रहमान तथा बचाव पक्ष से रविद्र कुमार सिन्हा, अनिल कुमार शर्मा एवं अमृत आनंद आदि ने अपना-अपना पक्ष रखा। सजा सुनाने के दौरान न्यायालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। 13 वर्ष पूर्व 25 नवंबर 2008 को सरेशाम अपराधियों ने उस समय पत्रकार विकास रंजन को गोली मार दी थी जब वे गायत्री मंदिर रोड स्थित अखबार के दफ्तर से कार्य निष्पादन कर घर जाने के लिए बाइक पर सवार हो रहे थे।

संध्या करीब 5-45 बजे हुई थी। इस संबंध में पत्रकार के पिता फुलकांत चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई रोसड़ा थाना कांड संख्या 173 /2008 में 13 लोगों को नामजद तथा तीन अज्ञात को आरोपित किया गया था। उन्होंने गोली मारने वाले अपराधियों का हुलिया बताते हुए देखने पर पहचानने का दावा किया था। वादी ने घटना के कारणों में अपने पट्टीदारों से पूर्व से चले आ रहे विवाद के साथ-साथ बाजार में अवैध धंधों का पर्दाफाश करना तथा समस्तीपुर के एक संवाददाता का जमानतदार बनना बताते हुए इससे जुड़े सभी व्यक्तियों द्वारा ही साजिश के तहत अपने पुत्र विकास रंजन की हत्या करने का दावा किया था।

सीआईआरएफ योजना के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति दी जाए

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर मुख्यमंत्री चौहान ने किया अनुरोध

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि रोड प्रगति का आधार हैं और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में सड़कें अभिन्न आधारभूत ढांचा है। मध्यप्रदेश ऐसे सड़क निर्माण का प्रयास कर रहा है, जिसके दोनों तरफ आर्थिक कलस्टर, औद्योगिक पार्क तथा टाउनशिप हों, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क और आधारभूत ढांचा फंड (सीआईआरएफ) योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गजे है। इनमें से केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी के इंदौर प्रवास के दौरान लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लगभग 844 करोड़ रुपए लागत की 15 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिसमें न्यूनतम भू-अर्जन के कारण त्वरित क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही ग्वालियर, भोपाल और सीहोर की 909 करोड़ लागत की चार नवीन परियोजनाओं की अनुशंसा की गई है। सीएम ने सीआईआरएफ योजना में इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया। श्री चौहान ने नसरुल्लागंज से संदलपुर (38 किलोमीटर) और बुधनी से बाड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग 146-बी के विस्तारित रूप में स्वीकृत कर फोर लेन में उन्नयन करने की स्वीकृति का भी निवेदन किया। सीएम ने अटल प्रगति पथ से संबंधित प्रस्तावित परियोजनाओं के ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज इत्यादि से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं शासकीय, निजी और वन भूमि के भू-अर्जन की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी।

गडकरी ने दी नर्मदा एक्सप्रेस-वे को भारत माला में शामिल करने की मंजूरी

सीएम ने बताया कि अटल प्रगति पथ के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 90 प्रतिशत भूमि एनएचएआई को दिसंबर 2021 तक हस्तांतरित कर दी जाएगी। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को नर्मदा एक्सप्रेस-वे के 906 किलोमीटर के अलाइनमेंट प्रस्ताव से भी अवगत कराया। श्री चौहान ने बताया कि मप्र के पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी सीमा में गुजरात तक प्रस्तावित अलाइनमेंट मप्र के 10 जिलों से होकर गुजरता है। श्री चौहान ने जानकारी दी कि वार्षिक योजना में शामिल शहडोल और बड़वानी जिलों के 130 किलोमीटर के फीडर रूट्स की स्वीकृति अपेक्षित है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे को भारत माला में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की। सीएम ने बताया कि मंत्रालय की परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ शहरों में बायपास के कार्य निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बायपास बनाने की आवश्यकता है। इस योजना में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर और खंडवा शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की रिंग रोड को आर्थिक प्रगति का आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र के प्रमुख शहरों को ब्राडगेज मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पीएस वित्त मनोज गोविल, पीएस लोक निर्माण नीरज मंडलोई, पीएस उद्योग संजय शुक्ला एवं मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन की प्रबंध निदेशक सुश्री छवि भारद्वाज उपस्थित थीं। अधिकारियों ने लोक निर्माण, वित्त, औद्योगिक विकास, मेट्रो रेल निर्माण की प्रगति, प्रदेश की एथनोल नीति तथा इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति का प्रस्तुतिकरण दिया।

केंद्रीय विद्युत मंत्री सिंह से मिले सीएम

सौर एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के प्रयासों की दी जानकारी

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात कर प्रदेश में हरित ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। श्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र सरकार की पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) पर भी विस्तार से चर्चा की।

आरडीएसएस योजना के क्रियान्वयन पर विस्तार से हुई चर्चा

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने बिजली के सेक्टर में अनेक नवाचार और परिवर्तन करने का फैसला किया है। योजनाओं के अंतर्गत पूरे बिजली सेक्टर का आधुनिकीकरण होगा और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे विद्युत सिस्टम को सुदृढ़ करने का फैसला लिया गया है। इसमें भारत सरकार 60 प्रतिशत अनुदान देगी और 40 प्रतिशत बिजली कंपनियों को व्यवस्था करना पड़ेगी। मध्यप्रदेश इस योजना से पूरी तरह सहमत है और हम अपने पूरे बिजली सिस्टम का आधुनिकीकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ग्रीन एनर्जी के उपयोग पर जोर है। मध्यप्रदेश इस दिशा में प्रयास ब?ा रहा है। हम तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि नीमच और आगर सौर ऊर्जा संयंत्रों में 2 रूपये 14 पैसे प्रति यूनिट की दर प्राप्त हुई। संयंत्रों का जल्द ही भूमि-पूजन किया जाना है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को ऊर्जा संयंत्रों के निरीक्षण के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में 300 सौर्य दिन मिलते हैं। इसमें मध्यप्रदेश तेजी से सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट और छतरपुर तथा मुरैना के सौर ऊर्जा प्लांट के प्रस्ताव के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रीवा का 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में पवन ऊर्जा, हाईब्रिड ऊर्जा और हरित ऊर्जा के भंडारण की जानकारी भी दी। उन्होंने कुसुम योजना में किसानों द्वारा अपने खेतों में सौर ऊर्जा उपकरणों और पम्पों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी बताया।

आरडीएसएस ऊर्जा क्षेत्र की क्रांतिकारी योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार की पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) ऊर्जा क्षेत्र की एक क्रांतिकारी योजना है। मध्यप्रदेश स्मार्ट मीटर अपनाने में अच्छी प्रगति कर रहा है। राज्य में लगभग 1.2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और 3.5 लाख मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 23.7 लाख मीटर की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया उन्नत चरण में है। मुख्यमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर पड़े गंभीर प्रभाव से वितरण कंपनी की बकाया सबसिडी के अग्रिम भुगतान के लिए राज्य को कम से कम दो साल का समय दिया जाना चाहिए। श्री चौहान ने शासकीय विभागों द्वारा वितरण कंपनी की बकाया राशि के भुगतान को एक किस्त की बजाय तीन किस्त में किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा प्रत्येक तिमाही में गैर अंकेक्षित खातों के प्रकाशन की आवश्यकता को शिथिल करते हुए योजना के पहले वर्ष के लिए वैकल्पिक बनाये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा। मुलाकात के दौरान केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल एवं प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट की।

बुधवार को भोपाल में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राजभवन में सौजन्य भेंट की।

हिंदू धर्म पर ही क्यों निशाना साधते हैं दिग्विजय सिंह : डॉ. मिश्रा

भोपाल । प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि वे हिंदू धर्म पर ही क्यों निशाना साधते हैं। डॉ. मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सिंह द्वारा हाल ही में दिए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि वह हिंदू धर्म और संत-महात्माओं को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब वे महंत नरेंद्र गिरि के परलोक गमन पर भी यह राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भगवा और हिंदू आतंकवाद की बात कहने वाले कांग्रेस के नेता हमेशा हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बनाते हैं।

कांग्रेस ने विधायकों के टूटने के डर से नहीं उतारा प्रत्याशी : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल । कांग्रेस द्वारा मप्र से राज्यसभा की एक मात्र रिक्त सीट पर अपना प्रत्याशी न उतारने को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इसे कांग्रेस की हार और पार्टी में बगावत का डर बताया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी खेमेबाजी और तनातनी इतनी ज्यादा है कि वह कभी भी दरक सकती है। ऐसे में कमलनाथ को डर लग रहा है कि अगर राज्यसभा चुनाव में वे उम्मीदवार खड़ा करते तो असंतोष और भड़क सकता था और शेष बचे विधायक भी इधर उधर हो सकते थे। कांग्रेस संभावित टूट से आशंकित है और घबरा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के पूरे संगठन पर कब्जा किया हुआ है और वे नहीं चाहते कि कोई अन्य नेता ताकतवर बने या हाइलाइट हो। कांग्रेस के भीतर असंतोष का यही सबसे बड़ा कारण है। स्वाभाविक है ऐसे में यदि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव लड़ने का मन बनाती तो कमलनाथ के खिलाफ अंदरखाने में सुलग रहा असंतोष विस्फोटक हो सकता था।

तो मंत्रालय में सिर्फ आनंद ही आनंद दिखेगा : केके मिश्रा

भोपाल । राजधानी भोपाल के मिंटो हाल में बुधवार को हुए एक सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा यह कहे जाने पर कि मंत्रालय में रंगीन पिक्चर ही दिखाई जाती है कि आनंद ही आनंद है, फील्ड में आनंद कहां तक पहुंचा है, आंख का इशारा देखकर अधिकारी काम करते हैं, विकास सब जगह और सही समय पर पहुंचना चाहिए, को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं प्रभारी मीडिया केके मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मिश्रा ने कहा कि एक सुनियोजित नीति के तहत विगत कई दिनों से सत्तासीन भाजपा, उसके नेताओं और मंत्रियों द्वारा अफसरशाही को निशाना बनाया जा रहा है। जब प्रदेश में तबादला उद्योग चलेगा, अफसरों से पार्टी फंड इकट्ठा करवाया जाएगा तो मंत्रालय सिर्फ आनंद ही आनंद दिखाएगा। सीएम यह भी बता दें कि उनके 16 वर्षीय कार्यकाल में आईएएस दंपती अरविंद. टीनू जोशी को भ्रष्टाचार से नवाजने वाले संरक्षक भी कौन थे। श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्य मंत्रित्वकाल के 16 साल बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री को यह तत्वज्ञान प्राप्त होना जहां आश्चर्यजनक है, वहीं यह भी स्मरण करा रहा है कि उन्हीं की सरकार ने जहां आनंद मंत्रालय का गठन किया हो, आनंद जनता को नहीं, भाजपा नेताओ, मंत्रियों और अफसरशाही को मिल रहा हो, वहां अब ठगी जा चुकी जनता के विकास की सुध आना आश्चर्यजनक है। मिश्रा ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में हर मोर्चे पर असफल हो चुकी सरकार का एक मेगा फेशन-शो चल रहा है, जिसमें यदि कोई काम अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय भाजपा को प्राप्त हो रहा है और असफलता के ठीकरा अफसरों के सिर पर फोड़ा जा रहा है।

प्रदेश में कानून का खौफ खत्म

भोपाल । मप्र में आए दिन हो रहे अपराध को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार और कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। नाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस तरह के दृश्य आम हो चुके हैं। लोगों में क़ानून का खौफ खत्म हो चुका है, लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। चाहे प्रदेश में नीमच की घटना हो या नेमावर, इंदौर, उज्जैन, देवास, रीवा, सतना, डबरा, बालाघाट की या धार जिले के गंधवानी की यह घटना। प्रदेश ऐसी घटनाओं से देश भर में रोज शर्मशार हो रहा है। मानवता, इंसानियत रोज कलंकित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा

नगरों की प्लानिंग में छोटा व्यवसाय करने वालों का स्थान निर्धारित हो

सीएम ने किया बीडीए के 551 आवासों और पांच विद्युत सबस्टेशन समेत कई विकास कार्यों का ई-लोकार्पण

बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय क्षेत्रों में विकास-कार्यों का लोकार्पण और नगर विकास के लिए राशि अंतरित कार्यक्रम को संबोधित किया।

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। श्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपए की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के बुधवार को यहां मिंटो हॉल में लोकार्पण किया। जिसमें राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी के महालक्ष्मी आवसीय योजना में निर्मित 551 प्रकोष्ठ एंव भोपाल विकास प्राधिकरण की लक्ष्मीनारायण शर्मा एयरोसिटी चरण-1 में 33/11 के. वी. क्षमता के पांच विद्युत सब स्टेशन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में उद्योग स्थापित हों पर इसके साथ ही हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की 299.40 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। लोकार्पित कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना, बस स्टेण्ड विकास, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रेफिक मैनेजमेंट, लायब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकाय जारी ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल पूर्ति, और जल संरक्षण पर करेंगे।

407 नगरीय निकाय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े: कार्यक्रम कन्या-पूजन और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुआ। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, विधायक कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव नगरीय विकास मनीष सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकाय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने विभागीय गतिविधियों तथा भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

बीडीए का महत्कांक्षी प्रोजेक्ट है महालक्ष्मी परिसर

राजधानी के हृदय स्थल पर स्थित महालक्ष्मी आवासीय परिसर योजना के 551 प्रकोष्ठों का बुधवार को सीएम ने ई-लोकार्पण किया। गौरतलब है कि यह बीडीए का महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है 196.80 करोड़ की लागत से इन प्रकोष्ठों का निर्माण किया गया है। जिसमें जी टाइप के 320, एफ टाइप के 180 तथा एच टाइप के 51 प्रकोष्ठ शामिल हैं। इन आवासों को शासकीय अधिकारीयों एंव कर्मचारियों को आवंटित किया जाना है। महालक्ष्मी परिसर को बीडीए ने ही बनाया है। जो कि सर्वसुविधा युक्त आवासीय योजना है, इसमें कम्यूनिटी हॉल, जॉगिंग ट्रेक, पार्क आदि सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही इंडोर विद्युत सबस्टेशन, जल आपूर्ति हेतु 4 लाख लीटर क्षमता वाला सम्पवेल और एसटीपी भी बनाया गया है।

बीडीए ने 1861 लाख से बनाए पांच विद्युत सब-स्टेशन

इसके साथ ही बीडीए द्वारा लक्ष्मीनारायण एयरोसिटी चरण -1 के तहत 1861 लाख की लागत से तैयार पांच विद्युत सबस्टेशनों का भी ई-लोकार्पण सीएम द्वारा कार्यक्रम में किया गया है। उल्लेखनीय है कि 217.66 हेक्टे. में बीडीए द्वारा विकसित की जा रही एयरो सिटी फेज-1 में 6326 भूखंड विकसित किए गए हैं। उक्त विद्युत सबस्टेशनों से इन भूखंडों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना में बीडीए द्वारा 45 मीटर मास्टर प्लान सड़क भी बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास होने के कारण यह परियोजना काफी अहम है, साथ ही यहां सीबीएसई के मुख्य कार्यालय एंव प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण भी किया जा रहा है।

प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में

श्री चौहान ने कहा कि शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में रह रही है, यह संख्या और बढ़ेगी। शहरों को गंदगी, प्रदूषण, बीमारी, अपराध और माफिया मुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता की है। स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर लगातार देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर शहर ने चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। भोपाल देश की स्वच्छतम स्व:संवहनीय राजधानी है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड मध्यप्रदेश को मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 296 निकाय ओडीएफ प्लस आए हैं। इंदौर को देश का पहला वॉटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। श्री चौहान ने लोकार्पित विकास कार्यों से जुड़े हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया।

सीएम आज करेंगे किसानों को लाभांवित करने बीज ग्रामों का शुभारंभ

भोपाल में होगा राज्य-स्तरीय कार्यक्रम

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन-कल्याण और सुराज अभियान में 23 सितंबर को दोपहर तीन बजे मिंटो हॉल में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत बीज ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इससे लाखों किसान लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण के साथ कृषि अधोसंरचना निधि में राशि का वितरण और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, यू-ट्यूब, फेसबुक लाइव और वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म-दिन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में लाखों किसानों को लाभांवित किया जाएगा। कृषि विभाग के बीज ग्रामों का शुभारंभ होगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें प्रत्येक बीज ग्राम में 50 हितग्राही किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि 10 जिलों में बीज ग्राम चयनित किए गए हैं। शाजापुर जिले में 9, उज्जैन में 8, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा और सिवनी में 7-7 ग्राम, राजगढ़ और बड़वानी 8-8 तथा हरदा के 10 ग्राम चयनित किए गए हैं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सीएम कार्यक्रम में किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण करेंगे।

प्रदेश में विकास सिर्फ घोषणाओं और कागजों पर

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में विकास कार्यों को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विगत 16 वर्षों से झूठ बोलकर सरकार चलाने का आरोप लगाया है। नाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शिवराज जी हकीकत तो यह है कि पिछले 16 वर्षों से आप जनता को मुंह चला कर, झूठी घोषणाओं, झूठे भूमि पूजन, झूठे शिलान्यास, झूठे नारियल फोड़कर रोज नकली रंगीन पिक्चर ही तो दिखा रहे हो। फील्ड में जाओ तो सब ब्लैक एंड वाइट ही ब्लैक एंड वाइट। उन्होंने कहा कि विकास पूरी तरह से नदारद है विकास सिर्फ घोषणाओं व कागजों पर ही नजर आता है, जमीनी धरातल पर स्थिति शून्य। जो काम आप पिछले 16 वर्षों से कर रहे हो, वही काम आज भी रोज कर रहे हो। आज भी चुनावी क्षेत्रों में जनदर्शन यात्रा निकालकर, जनता को गुमराह करने के लिए, रोज झूठी घोषणाएं कर झूठी रंगीन पिक्चर दिखा रहे हो, झूठे सपने दिखा रहे हो। कमलनाथ ने एक बार फिर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप कलाकारी इतनी अच्छी कर लेते हो, झूठी रंगीन पिक्चर इतनी दिखाते हो कि आपको तो अदाकारी के लिए मुंबई चले जाना चाहिए।

प्रदेश में 27 सितंबर को पुनः टीकाकरण महाअभियान

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 27 सितंबर को पुनः टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में प्रमुखता से प्रदेश के उन पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जाएगी, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। महाअभियान में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन प्रथम डोज लग जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्व महाअभियानों की तरह इस महाअभियान में भी जन-भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सीएम आज करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से चर्चा

इस सिलसिले मे मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे जिला, विकासखण्ड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाना है। इसके लिए वैक्सीन कारगर उपाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की निः शुल्क उपलब्धता करवा कर पुण्य का काम किया है। अब हम सबका दायित्व बनता है कि सभी पात्र लोग वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक वैक्सीनेशन में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उसमें जन-भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। जिला, विकासखण्ड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाकर पूर्व के दो टीकाकरण महाअभियान को सफलता दिलाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे टीकाकरण महाअभियान में भी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता से सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

आप सभी ने जो प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद : डॉ. मुरुगन

भाजपा अजा मोर्चा ने किया केंद्रीय राज्यमंत्री का स्वागत

भोपाल (एजेंसी)। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने तमिलनाडु के कार्यकर्ता को मध्यप्रदेश से राज्यसभा में भेजने का निर्णय किया है। यह बात राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार डॉ. एल मुरुगन ने बुधवार को अजा मोर्चा द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कही।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा बुधवार को डॉ मुरुगन का प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत मोर्चा के प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक, कविता पाटीदार, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर, अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ कैलाश जाटव, महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नारोलिया, मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सतीश मालवीय आदि ने डॉ मुरुगन का स्वागत किया। स्वागत समारोह में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा उम्मीदवार डॉ एल मुरुगन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपीनड्डा , मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं मध्यप्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि मुझे मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनने का अवसर दिया है। डॉ मुरुगन ने कहा कि मध्यप्रदेश मेरे लिए नया नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर यहां आने और काम करने का अवसर मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे जितना प्यार मध्यप्रदेश में मिला है, मेरे नामांकन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने जो आत्मीयता दिखाई है और जितने उत्साह से मेरा स्वागत किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं।

इस अवसर पर अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कहा कि मैं डॉ मुरुगन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने एवं राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि डॉ मुरुगन के मंत्री और राज्यसभा सदस्य बनने से अजा मोर्चा की ताकत बढ़ेगी।

वित्त मंत्री देवड़ा से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. मुरुगन

बुधवार को भोपाल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन की प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से उनके निवास पर सौजन्य भेंट हुई।

एक्ट्रेस पायल घोष

ने किया बड़ा दावा, कहा- अज्ञात हमलावरों ने एसिड डालने की कोशिश की, दिखाए चोट के निशान

मुंबई के अंधेरी इलाके में फेमस एक्ट्रेस पायल घोष को अज्ञात हमलावरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. उन्होंने एक्ट्रेस पर एसिड डालने की भी कोशिश की. एक्ट्रेस ने इस बात का दावा किया है.

एक्ट्रेस के मुताबिक, वह मुंबई के अंधेरी इलाके से अपने घर लौट रही थीं. वह अपने कार में बैठने ही वाली थीं कि अचानक किसी ने उनपर हमला कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया कि शख्स के पास एसिड भी था और उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था. एक्ट्रेस के हाथ में मामूली चोट आई है.

एक्ट्रेस ने बताई पूरी आपबीती

पायल ने दावा किया, मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली थी और कुछ लोग आए और हाथों में एसिड लेकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की. इसके बाद मैं मदद के लिए चिल्लाई और वे वहां से भाग गए. उन्होंने मुझे मेरे सिर पर रॉड से मारा लेकिन सौभाग्य से सिर पर कोई चोट नहीं आई और हाथ में भी चोट लगी है. उन्होंने मुझे हाथों पर भी मारा है. मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी. मैं अपने भाई के साथ जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगी.

अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं पायल

बता दें कि एक्ट्रेस पायल घोष ने मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी. इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट कर पीएम मोदी से भी मदद मांगी. हालांकि ये मामला कुछ साल पुराना बताया गया था. कश्यप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. पुलिस ने अनुराग कश्यप से इन आरोप के सिलसिले में पूछताछ भी की थी.

मीरा राजपूत का ये टैलेंट देखकर हैरान रह गए पति शाहिद कपूर, वीडियो देख तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस

साथ जुड़ी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई दे जाती हैं। वहीं, हाल ही में वो अपने एक ऐसे ही पोस्ट के कारण चर्चाओं में आ गई हैं। उन्होंने अपने सोशल एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मीरा ने अपने एक टैलेंट का खुलासा किया है। उनका ये टैलेंट देखकर पति शाहिद कपूर भी हैरान हैं। वीडियो में मीरा को फैंस की तारीफें मिल रही हैं।

मीरा राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने चेहरे को मास्क से कवर किए हुए हैं और पियानो प्ले करती दिख रही हैं। मीरा इस दौरान कई तरह की धुन प्ले कर रही हैं। उन्होंने पियानो पर अपने पति शाहिद कपूर के लिए उनकी फिल्म कबीर सिंह के गाना बेख्याली की धुन भी प्ले की। वीडियो में शाहिद कपूर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो मंत्रमुग्ध होकर पियानो की धुन सुन रहे हैं।

इस वीडियो के शेयर करते हुए मीरा ने कैप्शन में लिखा- %आप मेरे बारे में ये नहीं जानते होंगे। मैं पियानो प्ले कर सकती हूं! खैर मैंने काफी समय से प्रैक्टिस नहीं की है लेकिन मैं म्यूजिक पढ़ सकती हूं, स्केल्स प्ले कर सकती हूं और सुनते ही उसकी धुन प्ले कर सकती हूं। मैं दोबारा प्ले करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हूं। मैं अपने लेसन्स से नफरत करती थी शायद इसलिए क्योंकि इसका एक्जाम लिया जाता था। लेकिन अब मैं इसे छोड़ने के लिए बहुत पछताती हूं! जब भी मैं पियानो देखती हूं तो फौरन बैठकर प्ले करने लगती हूं। लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। अब मैं सोचती हूं कि ये वापस से शुरू किया जाए।

रणवीर सिंह से इंस्टा पर दीपिका पादुकोण ने पूछा सवाल, एक्टर बोले- खाना गर्म कर लो बेबी...

बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में गिने जाने वाले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से अकसर प्यार का इजहार करते दिखाई दे जाते हैं। वहीं, हाल ही में ये दोनों एक बार फिर से कुछ ऐसे ही कारणों से चर्चाओं में आ गए हैं। रणवीर सिंह से इंस्टाग्राम पर उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में एक्टर ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कुछ ऐसा कह दिया कि इंटरनेट पर इसकी चर्चाएं शुरू हो गईं।

दरअसल, हाल ही में रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपने फैंस के सवालों का जवाब देने के लिए आस्क मी एनीथिंग सेशल रखा। इस दौरान उन्होंने फैंस के कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते दौरान कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और खास दोस्तों का भी नाम लिया। जिनमें अर्जुन कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक शामिल हैं। वहीं, इस बीच उनके चैट सेशल में दीपिका पादुकोण का भी सवाल आ गया। दीपिका ने पूछा- घर कब आ रहे हो?... इस पर रणवीर सिंह ने जवाब दिया- खाना गर्म कर लो बेबी, मैं अभी बस पहुंच ही गया हूं।

दीपिका, रणवीर की इस तरह की क्यूट बातचीत पहले भी देखने को मिल चुकी है। रणवीर जब भी इंस्टा पर चैट सेशन रखते हैं, दीपिका उनसे मजेदार सवाल पूछती दिखाई दे जाती हैं। बता दें कि इन दिनों रणवीर सिंह आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी हैं। रणवीर सिंह की कई फिल्में रिलीज होने को हैं। जिनमें 83 के साथ-साथ कई और फिल्में शामिल हैं।

जाह्नवी कपूर

ने शेयर की पार्टी Photos, साथ में नजर आए रूमर्ड एक्स-बॉयफ्रेंड?

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस से जुड़ी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई दे जाती हैं। वहीं, हाल ही में वो अपने एक ऐसे ही पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपने सोशल एकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, इन फोटोज में जाह्नवी कुछ लोगों के साथ पार्टी करती दिखाई दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन तस्वीरों में खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर के कथित एक्स-बॉयफ्रेंड भी नजर आ रहे हैं।जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें वीडियोज और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन फोटोज और वीडियोज में जाह्नवी कपूर के साथ उनकी बहन खुशी कपूर दिखाई दीं। इस दौरान जाह्नवी के साथ उनके खास दोस्त अक्षत राजन भी दिखाई दिए।

स्पॉटबॉय की रिपोर्ट की मानें तो अक्षत और जाह्नवी एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं और पार्टी में ये दोनों ए- दूसरे को हग और किसेस करते हुए काफी मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं।बताया जा रहा है कि ये

अक्षत की बर्थडे पार्टी का वीडियो हो सकता है। इस पोस्ट पर तस्वीरें, वीडियोज शेयर करते हुए जाह्नवी ने कैप्शन में लिखा- फैम... जिस पर फैंस की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस पार्टी में जाह्नवी कपूर व्हाइट रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं। इन फोटोज में वो बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आ रही हैं।

डरहम-ग्लूस्टरशायर काउंटी मैच के दौरान बीच मैदान पर उतरा हेलीकाप्टर

वाशिंगटन। आपने क्रिकेट मैच कई बार बीच में रुकते हुए सुने होंगे। जिसकी वजह, बारिश, खराब लाइट और बेकाकू दर्शक जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के ब्रिस्टल क्रिकेट मैदान पर एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैच के दौरान बीच मैदान पर हेलीकॉप्टर (एयर एंबुलेंस) को उतार दिया गया। जिसके वजह से करीब एक घंटे तक खेल बाधित रहा। क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाली यह अपने आप में हैरान करने वाली घटना थी।

पहले ओवर का खेल था जारी

इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के तहत 21 सितंबर को ग्लूस्टरशायर और डरहम के बीच मुकाबला शुरू हुआ। अभी पहला ओवर ही फेंका जा रहा था कि मैच अधिकारियों के पास एक खबर आई। यह सूचना सबको हैरान करने वाली थी। पता चला कि मैदान पर हेलीकाप्टर उतरने वाला है। हलीकॉप्टर जैसी ही नीचे आया सभी खिलाड़ी मैदान छोड़ कर बाहर चले गए।

मैदान के पास एक घर में था मरीज

बाद में एयर एंबुलेंस की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ग्रेट वेस्टर्न एयर एंबुलेंस ने अपने जारी बयान में कहा, हेलीकॉप्टर एक मरीज का इलाज कर बेस की ओर लौट रहा था, तभी जानकारी मिली की ब्रिस्टल क्रिकेट ग्राउंड के पास एक घर में मरीज गंभीर हालत में है, आसपास खाली जगह न होने की वजह स हेलीकॉप्टर को मैदान पर उतारने का फैसला किया गया।

जीत के बाद बोले संजू सैमसन- यह मजेदार रहा कि हम जीत गए

दुबई। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ रोमांचक मैच में 2 रन से शानदार जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए आई राजस्थान की टीम ने बिना 20 ओवर खेले 185 रन बनाए और टीम ऑलआउट हो गई। जवाब में पंजाब की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी निभाई। पर दोनों सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने मैच में वापसी कराई। आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट चटकाकर टीम को जीत हासिल करवाई। मैच के बाद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने कहा कि यह मजाक है पर हमें लग रहा था कि हम जीत सकते हैं।

सैमसन ने आगे कहा कि मैंने आखिरी ओवरों के लिए मुस्ताफिजुर रहमान और कार्तिक त्यागी के ओवर रखे हुए थे। क्रिकेट बहत ही मजाकिया खेल है। हम आखिरी पल तक लड़ते रहे और खुद पर भरोसा था। मैं हमेशा से विश्वास करता हूं कि मेरे गेंदबाज आखिरी पल तक लड़े जिस वजह से मैंने दो ओवर रखे थे। सैमसन ने आगे कहा सच कहूं तो इस पिच पर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमें गेंदबाजी करनी थी। अगर हम कैच पकड़ लेते तो मैच को आसानी से जीत सकते थे। खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस को लेकर काफी मेहनत की है।

बीसीसीआई ने नई आईपीएल टीमों के लिए निविदा प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को नयी आईपीएल टीमों के लिए निविदा दस्तावेज खरीदने की समय सीमा पांच दिन बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी। आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) की संचालन समिति ने 31 अगस्त को 10 लाख रुपए की निविदा फीस के भुगतान पर 'निविदा के लिए निमंत्रण (आईटीटी) दस्तावेज जारी किया था। यह रकम वापस नहीं (नॉन रिफंडेबल) होगी। बीसीसीआई के मुताबिक कि इच्छुक पक्षों के अनुरोध पर बीसीसीआई ने अब आईटीटी दस्तावेज खरीदने की तारीख को 10 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। बीसीसीआई की 2022 के सत्र में नयी टीमों को जोड़ने की योजना है और यह टीमें अहमदाबाद, लखनऊ या पुणे से हो सकती हैं।

शारजाह मास्टर्स शतरंज - भारत के सुनील नारायनन सयुंक्त बढ़त पर

शारजाह ,यूएई। पिछले वर्ष कोरोना के वजह से रद्द होने के बाद इस वर्ष एक बार फिर शारजाह मास्टर्स शतरंज का आयोजन ऑन द बोर्ड हो रहा है हालांकि इस बार खिलाड़ियों की संख्या सीमित करते हुए सिर्फ शीर्ष 60 खिलाड़ियों को प्रतियोगिता मे स्थान दिया गया है । प्रतियोगिता के स्तर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते है की 28 देशो के इन 60 खिलाड़ियों मे सभी टाइटल खिलाड़ी है, इसमें 42 ग्रांड मास्टर ,2 महिला ग्रांड मास्टर ,13 इंटरनेशनल मास्टर और 3 फीडे मास्टर खेल रहे है ।

अब तक खेले गए चार राउंड के बाद भारत के सुनील नारायनन 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ सयुंक्त बढ़त पर चल रहे है ,उन्होने अब तक मोरक्को के अदनानी मोक्लिस्स को ,पारागुए के डेलगाड़ो रेमरीज़ ,तुर्की के

यिलमाज मुस्तफा को हराया है जबकि ईरान के अमीन तबातबाई से बाजी ड्रॉ खेली है ।

राउंड 4 के बाद उनके साथ ईरान के अमीन तबातबाई ,यूएई के सलेम एआर सालेह और जॉर्जिया के मिखिल मचेडि्लश्विली भी इतने ही अंको पर है । अन्य भारतीय खिलाड़ियों मे अर्जुन एरिगासी , अभिजीत गुप्ता ,3 अंक , अधिबन भास्करन ,सूर्या शेखर गांगुली 2.5 अंको पर खेल रहे है ।

मैं वापसी के लिए अभी सबसे खराब स्थिति में हूं : रोजर फैडरर

ज्यूरिख। रोजर फेडरर का कहना है कि उनकी चोट के बाद वापसी उन्हें अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह सबसे खराब स्थिति में हैं। फेडरर इस साल दौरे पर वापस आने से पहले अपने दाहिने घुटने की दो सर्जरी के साथ एक साल से अधिक समय से बाहर थे। उन्होंने इस दौरान केवल 13 मैच खेले। जुलाई में विंबलडन में क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने तीसरा ऑपरेशन करवाया था। स्विस स्टार ने ज्यूरिख में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। पुनर्वसन की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा हूं।

मेरे पीछे सबसे बुरा है। मैं आने वाली हर चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब आप चोट से वापस आते हैं, तो हर दिन एक बेहतर दिन होता है। इसलिए यह एक रोमांचक समय है। उन्होंने कहा कि अपने घुटने में दर्द के कारण वह जो कुछ भी झेल रहे थे, उसे देखते हुए स्थिति से निपटना कोई मानसिक समस्या नहीं थी।

राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप

रोहित ने गत विजेता को हराकर जीता गोल्ड, शिवा समेत नौ खिलाड़ियों को मिला विश्व चैंपियनशिप का टिकट

बेल्लारी। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रोहित मोर ने गत विजेता हुसामुद्दीन को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। रोहित ने पुरुषों के 57 किग्रा भारवर्ग के फाइनल में मोहम्मद हुसामुद्दीन को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। रोहित के अलावा स्टार मुक्केबाज शिवा थापा और संजीत ने भी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए अपनी-अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

इंस्पायर इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट्स में खेले गए अन्य मुकाबलों में दीपक कुमार (51 किग्रा), आकाश (54 किग्रा), सुमित (75 किग्रा), सचिन कुमार (80 किग्रा), लक्ष्य (86 किग्रा) और नरेंद्र (+92 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीतकर एसएससीबी के दबदबे को कायम रखा। गोल्ड मेडल के साथ ही सभी विजेताओं ने विश्व चैंपियनशिप के लिए अपना टिकट भी पक्का कर लिया। ये सभी सर्बिया के बेलग्रेड में 24 अक्तूबर से 6 नवंबर तक विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिवा को छोड़कर बाकी के सभी मुक्केबाज पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लेंगे।

बात करें राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तो एसएससीबी ने यहां आठ गोल्ड मेडल समेत 12 पदक जीते और अपने टीम चैंपियनशिप के ख़िताब का बचाव किया। इसके अलावा रेलवे ने दो गोल्ड समेत सात मेडल्स के साथ दूसरे स्थान पर रही। एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक उनके शानदार प्रदर्शन

के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेठ मुक्केबाज घोषित किया गया। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से एक साल बाद आयोजित इस चैंपियनशिप में इस बार 35 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न बोर्ड से 400 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था।

राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप

अमलान, प्रवीण और मंजू बाला ने किया शानदार प्रदर्शन, अंतिम दिन जीते स्वर्ण पदक

जयपुर। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 60वें सीजन की समाप्ति यानी हो गई। चैंपियनशिप के अंतिम दिन असम के फर्राटा धावक अमलान बोरगोहेन, तमिलनाडु के त्रिकूद खिलाड़ी प्रवीण चित्रावेल और राजस्थान के तार गोला फेंक की अनुभवी खिलाड़ी मंजू बाला सिंह ने अपनी-अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। इन सभी ने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हुए सोने के तमगे हासिल किए।

अमलान ने पुरुष 200 मीटर फाइनल में 20.75 सेकेंड के समय के साथ खिताब जीता। अमलान पिछले 20 महीने में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 200 मीटर की स्पर्धा में हिस्सा ले रहे थे। अमलान ने करियर में पहली बार 21 सेकेंड से कम का समय लिया और नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया। 20 वर्षीय प्रवीण ने त्रिकूद में 16.88 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता। उनका पिछला निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16.51 मीटर था जो उन्होंने मार्च 2019 में बनाया था। सेना के अब्दुल्ला अबुबाकर ने 16.84 मीटर के निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता जबकि टीम के उनके साथी कार्तिक उन्निकृष्णन ने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी करते हुए 16.80 मीटर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। एशियाई खेलों के चैंपियन अरपिंदर 15.91 मीटर के प्रयास के साथ छठे स्थान पर रहे। एशियाई खेल 2014 की पदक विजेता मंजू अपने तीसरे

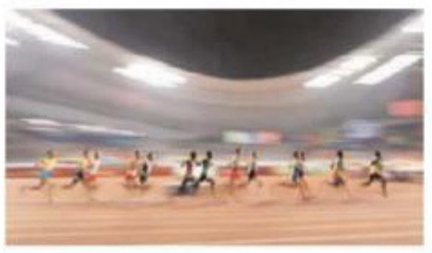

प्रयास में करियर के सर्वश्रेष्ठ 64.42 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। उन्होंने महिला तार गोला फेंक में हरदीप कौर के 61.67 मीटर के मीट रिकॉर्ड को तोड़ा जो 2002 में बनाया था। सेना के कार्तिक कुमार और महाराष्ट्र की संजीवनी बाबूराव जाधव ने पहली दिन 5000 मीटर की निराशा को पीछे छोड़ते हुए 10000 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। तमिलनाडु की अर्चना सुसींद्रन ने महिला 200 मीटर का खिताब अपने नाम किया। महिला 100 मीटर का खिताब जीतने वाली दिल्ली की तरनजीत कौर बेहद मामूली अंतर से 200 मीटर में दूसरे स्थान पर रहीं।

पंजाब की हार पर बोले केएल राहुल- इसे निगलना कठिन है

दुबई। पंजाब किंग्स को एक बार फिर से बढिया शुरूआत के बावजूद हार झेलनी पड़ी। राजस्थान से मिले 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब को आखिरी ओवर में महज 4 रन की जरूरत थी लेकिन कार्तिक त्यागी की गेंदबाजी के आगे वह दो रन से मैच गंवा बैठी। मैच गंवाने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि इसे निगलना कठिन है। हम ऐसी टीम रहे हैं जिसने पहले भी इस तरह के खेलों का अनुभव किया है। हमें यह देखने की जरूरत है कि हम दबाव को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं।

केएल राहुल ने कहा कि 18वें ओवर में मैच को खत्म करने की कोशिश में कभी-कभी आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपना रास्ता खो देते हैं। इससे विरोधियों को अंदर

आने का मौका मिल जाता है। हमने पिछली गलतियों से नहीं सीखा है। अब हम मजबूत वापसी करने और अगले 5 मैच जीतने की कोशिश करेंगे। हमने गेंद से चीजों को अच्छी तरह से वापस खींचा, विकेट लेते रहे, जो इस प्रारूप में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए, मयंक और यहां तक कि एडेन के लिए अपने पहले आईपीएल मैच में रन बनाना महत्वपूर्ण था।

बता दें कि पंजाब की टीम ने 2020 में खेले गए मुकाबले में भी ठीक ऐसे ही मुकाबला गंवाया था। पंजाब ने राजस्थान के खिलाफ ही यह मैच गंवाया था। इसमें ओपनिंग क्रम राहुल और गेल ने 120 रन बनाए थे। 2021 के इस सीजन में भी पंजाब को जीत के लिए 185 रनों की जरूरत थी। मयंक और राहुल ने पहले विकेट के लिए राजस्थान के ही खिलाफ 120 रन बनाए। लेकिन बावजूद पंजाब की टीम को हार झेलनी पड़ी।

नस्लीय मामले में हंगरी पर फीफा की बड़ी कार्रवाई, लगाया सबसे बड़ा जुर्माना

लंदन। फीफा ने बुडापेस्ट में इंग्लैंड खिलाफ मैच के दौरान हंगरी के समर्थकों द्वारा नस्लीय दुर्व्यवहार करने पर फुटबॉल विश्व कप के अगले क्वालीफायर मैच को दर्शकों के बिना खेलने की सजा सुनाई है। फीफा ने इसके साथ ही हंगरी के फुटबॉल महासंघ पर दो लाख स्विस फ्रैंक (2,17,000 डॉलर यानी लगभग 1.60 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया है। यह इस खेल की वैश्विक शासी निकाय द्वारा किसी देश पर लगाए गए सबसे बड़े वित्तीय दंड में से एक है।

फीफा ने कहा कि मामले की सभी परिस्थितियों का विश्लेषण और विचार करने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए समिति ने फैसला किया कि (हंगरी) फीफा प्रतियोगिताओं में अपने अगले दो घरेलू मैच दर्शकों के बिना खेलेगा, दूसरा मैच दो साल की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए निलंबित रहेगा।

रोनाल्डो ने खत्म की मेसी की बादशाहत, 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने

लंदन। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़कर 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक, इस सीजन में शीर्ष दस कमाई करने वाले फुटबॉलरों की कर युक्त आय 585 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जोकि पिछले साल 570 मिलियन डॉलर से ज्यादा है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा हैं जबकि मेसी पीएसजी के साथ खेलने का करार किया है।

पीएसजी में सबसे अधिक वेतन पाने वाले तीन फुटबॉलर

पेरिस सेंट जर्मन क्लब में सबसे अधिक कमाई करने वाले पांच में से तीन फुटबॉलर शामिल हैं। इस वर्ष मेसी ने भी पीएसजी की ओर से खेलने का फैसला किया था। उनके अलावा 29 वर्षीय नेमार भी इसी क्लब का हिस्सा हैं जो इस साल कमाई के मामले में तीसरे स्थान पर हैं और उनकी कमाई 95 मिलियन डॉलर रही। जबकि 22 वर्षीय कैलियन म्बाप्पे चौथे नंबर पर काबिज हैं जिन्होंने इस साल 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की।

2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर

नाम	कुल कमाई (डॉलर में)
क्रिस्टियानो रोलनाल्डो	125 मिलियन
लियोनेल मेसी	110 मिलियन
नेमार	95 मिलियन
कैलियन म्बाप्पे	43 मिलियन
मोहम्मद सालेह	41 मिलियन
रॉबर्ट लेवानडॉस्की	35 मिलियन
एंड्रेस इनिएस्टा	35 मिलियन
पॉल पोग्बा	34 मिलियन
गैरेथ बेल	32 मिलियन
ईडन हैजर्ड	29 मिलियन

राजस्थान की रोमांचक जीत, लेकिन कप्तान सैमसन पर हुई कार्रवाई, लगा जुर्माना

दुबई । दुबई में खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स पर दो रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। पंजाब को मैच जिताने में कार्तिक त्यागी ने अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंकतालिका में पांचवें नंबर पहुंच गया और उसकी प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। लेकिन हल्लाबोल राजस्थान के लिए इस जीता का मजा उस समय किरकरा हो गया जब उसके कप्तान संजू सैमसन पर जुर्माना लगाया गया।

सैमसन पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान उन पर धीमी ओवर रेट के चलते 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया, जहां तक आईपीएल की आचार संहिता के मुताबिक निर्धारित समय में कम से कम ओवर फेंकने की बात है तो इस सीजन में पंजाब किंग्स ने पहली बार यह

अपराध किया है।

राजस्थान ने अंतिम ओवर में दर्ज की रोमांचक जीत

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए। जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 49 और महिपाल लोमरोर ने 43 रनों की पारियां खेलीं।

पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए उनके अलावा मोहम्मद शमी तीन खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रहे। 186 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने बेहतरीन शुरुआत करते पहले विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी की।

अंतिम ओवर में जब पंजाब को जीतने के चार रन बनाने थे तो कार्तिक त्यागी ओवर फेंकने आए। उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ एक देकर दो विकेट झटके। जिसके चलते पंजाब यह मैच 2 रनों से हार गया।

अंकतालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा राजस्थान

पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली दो रनों की रोमांचक जीत के साथ राजस्थान की टीम अंकतालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई। उसने आईपीएल 2021 में 8 मैच खेले जिसमें 4 जीते और 4 हारे हैं। अब राजस्थान के 8 अंक हैं और उसे अभी 6 मैच खेलना बाकी है। कुल मिलाकर उसकी प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं।